सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जो है, "जितना" है उसी में खुश रहना सीखो मेरे दोस्त क्योंकि जरूरत से ज्यादा "रौशनी" भी इंसान को अंधा बना देती हैं ।

वर्ष 01, अंक 157, नई दिल्ली

रविवार, 20 अगस्त 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

विपक्षी नेता साबित करें, मैं हर सजा के लिए तैयार

द्वारका एक्सप्रेस-वे घोटाले पर गडकरी का जवाब

संजय बाटला

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मैंने 50 लाख करोड़ का काम करवाया है। उन्होंने कहा कि जिस द्वारका एक्सप्रेसवे पर सीएजी रिपोर्ट को विपक्ष घोटाला बता रहा है, वह ठीक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को भी चुनौती दी।

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे में घोटाले के आरोपों को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर सीएजी की रिपोर्ट को भी गलत ठहराया। गडकरी ने साफ कहा कि हमने द्वारका एक्सप्रेस वे में निर्माण के खर्च को कम किया है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 12 फीसदी पैसा बचाया गया है। गडकरी के अनुसार विपक्षी नेता अगर एक्सप्रेसवे के निर्माण में घोटाला साबित कर दें तो वो हर सजा के लिए तैयार हैं।

तो मैं वहीं करुंगा जो आप कहेंगे

केंद्रीय मंत्री ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा कि द्वारका एक्सप्रेस-वे 29 किलोमीटर का हाईवे है। इसमें 6 टनल हैं। इसके लिए निकाले गए टेंडर में रेट 206 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने हाईवे के निर्माण में 12 फीसदी पैसा बचाया है। गडकरी ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर है। यह लगभग 230 किलोमीटर लंबा था, क्योंकि इसमें सुरंगें भी शामिल थीं। उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में खर्च को कम किया गया है। गडकरी ने कहा, AAP से लेकर विपक्ष के नेताओं को मेरा आह्वान है कि एक बार सिद्ध कर दीजिए कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं वहीं करूंगा जो आप कहेंगे।

सीएजी रिपोर्ट में क्या था ?

हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। इस रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में अधिक खर्च की बात कही गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 29.06 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को अत्यधिक लागत पर बनाने की बात कही थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस हाईवे को 250.77 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर के खर्च पर बनाया गया। वहीं, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की तरफ से इस हाईवे के लिए 18.2 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर की राशि स्वीकृत की गई थी।

advertisement Tariff
w.ef. 1st January 2023

परिवहन विशेष
दिल्ली, एनसीआर से प्रसारित लोकप्रिय साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र

in Rs. / Sq. Cm.

	Basic	3rd Page	Back Page	Front Page Semi Solus	Fornt Page Solus
Delhi Aur Delhi	BW - Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Delhi	100*	200*	250*	300	300

Special Instructions:-
- Innovation on any page will be accepted at a premium of 100% on applicable card rate.
- Any specified position will be accepted at a premium of 25% on applicable card rate.
- B/W advertisement on page 3/Back will charged at colour rate.
- Classified display advertisement will be charged on basic display rate.
- Pointers 4x4 sq. C. or 5x4 sq. cm. will be charged as per card rate.
- box reply charges (each box) will be charged Rs. 150/-
- Political advertisement - as applicable.

परिवहन विशेष में विज्ञापन के लिए ऑनलाईन भुगतान सीधे बैंक खाते/फ़ोन पे पर कर सकते हैं और विज्ञापन के मैटर के साथ ऑनलाईन भुगतान की रसीद व्हाट्सऐप नंबर 09212122095 या newstransportvishesh@gmail.com पर भेज सकते है। भुगतान करने के लिए *NEFT / IMPS / RTGS*
Account Name:-Transport Vishesh Limited
IFSC CODE :- INDB0001396
Cur Account no :- 259212122095
या Phone pay :- 9212122095

शिमला, बद्दी और कुल्लू मनाली नहीं जा रही अंबाला से रोडवेज की बसें, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद

अंबाला से हिमाचल के बद्दी के लिए रोजाना हरियाणा रोडवेज की विभिन्न डिपो की 12 बसें जाती थी। हिमाचल में हुए भूस्खलन के बाद कुछ बसें अंबाला से वाया नाहन होते हुए शिमला जा रही थी, लेकिन अब वह बसें भी बंद है।

परिवहन विशेष न्यूज

अंबाला। हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन के कारण जगह जगह मलबा गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। सड़कें टूटने से परिवहन निगम का बस रूट प्रभावित हुआ है। जिसके चलते शिमला, बद्दी और कुल्लू मनाली की सड़कों पर अंबाला से यातायात प्रभावित है। अंबाला से शिमला, बद्दी व कुल्लू मनाली की बस नहीं जा पा रही हैं। हालांकि कुछ बसें हिमाचल में मंडी तक जा रहीं हैं।

वहीं, हिमाचल परिवहन की दो बसें इस रूट पर यात्रियों को ले जा रही हैं। बता दें कि हिमाचल में हुए भूस्खलन के बाद कुछ बसे अंबाला से वाया नाहन होते हुए शिमला जा रही थी, लेकिन अब वह बसें भी बंद है। इसी तरह से अंबाला से शिमला के लिए अंबाला डिपो की करीब चार बसें शिमला को जाती थी मगर वह कई दिनों से बंद हैं। जबकि दूसरे राज्यों की करीब 25 बसें शिमला जाती थी, जोकि अब नहीं जा रही हैं।

अंबाला से बद्दी

अंबाला से हिमाचल के बद्दी के लिए रोजाना हरियाणा रोडवेज की विभिन्न डिपो की 12 बसें जाती थी। इसके अलावा अन्य राज्यों की करीब 35 बसें बद्दी जाती थी लेकिन अब वह भी नहीं जा पा रही हैं।

अंबाला से कुल्लू मनाली

अंबाला से कुल्लू मनाली के लिए हरियाणा रोडवेज के विभिन्न डिपो की 5 बसें जाती थी और अन्य राज्यों की 10 बसें कुल्लू मनाली जाती थी। अंबाला डिपो की अभी तक कुल्लू मनाली की सर्विस बंद है। अन्य बसें कुल्लू मनाली के यात्रियों को मंडी तक लेकर जा पा रही हैं।

इस रास्ते से जा रही हिमाचल डिपो की बस

हिमाचल डिपो के परिचालक पवन शर्मा ने बताया कि शिमला का मार्ग खुल गया है और वह चालक के साथ शिमला से बस में यात्रियों को लेकर खरेटा, ऊना, आनंदुपर, नालागढ़ से अंबाला होते हुए दिल्ली गए थे। इसके बाद वह दिल्ली से अंबाला छावनी पहुंचे हैं लेकिन अब वापस शिमला जा रहा है।

एक्सप्रेसवे पर बनेंगे नए औद्योगिक गलियारे, खुलेंगी 500 इकाइयां, खर्च होंगे चार हजार करोड़

यूपी के एक्सप्रेस वे पर नए औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे और इसके आसपास 500 औद्योगिक इकाइयां विकसित की जाएंगी। हर गलियारे के लिए 100 एकड़ का भूमि अधिग्रहण होगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

परिवहन विशेष न्यूज

लखनऊ। उद्योगों को रफ्तार देने के लिए डिफेंस और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बाद एक्सप्रेसवे औद्योगिक गलियारे कागजों से बाहर निकलकर जमीन पर उतरने लगे हैं। बुंदेलखंड, आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ औद्योगिक पार्कों की स्थापना को हरी झंडी मिल गई है। इससे प्रदेश में 500 से ज्यादा बड़ी औद्योगिक इकाइयों के खुलने का रास्ता भी साफ हो गया है।

यूपीडा इन चारों एक्सप्रेसवे के इंट्री व एग्जिट प्वॉइंट पर गलियारे के निर्माण के लिए 100-100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगा। गंगा एक्सप्रेस- वे से इसका आगाज हो गया है। 500 बड़ी इकाइयों की स्थापना को ध्यान में रखकर इस मेगा प्रोजेक्ट में करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसको लेकर कार्ययोजना तैयार हो गई है। इसमें एक्सप्रेसवे के सहारे उद्योगों के विकास का ब्लू प्रिंट बनाया गया है।

एक्सप्रेसवे के इंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर उद्योग लगाने के लिए कॉन्सेप्ट प्लान, परस्पेक्टिव प्लान, प्री फिजिबिलिटी और डीपीआर तैयार करने का जिम्मा यूपीडा को सौंपा गया है। योजना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि औद्योगिक गलियारे के लिए पहले चरण में सौ-सौ एकड़ जमीन अधिग्रहण के बाद दूसरे चरण में मांग के अनुरूप और जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

यूपीडा के मुताबिक चारों एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ी होने वाली इकाइयां राज्य के किसी भी कोने में अधिकतम 12 घंटे में अपने उत्पाद पहुंचाने में सक्षम होंगी। इससे सबसे ज्यादा विकास लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस सेक्टर का होगा। इसी के साथ इनमें भंडारण वाले उत्पादों की मांग में तेजी आएगी। एक्सप्रेसवे के औद्योगिक गलियारों के जरिए फल-सब्जी व डेयरी उत्पादों सहित ऐसी वस्तुओं के परिवहन की रफ्तार तीन गुना तक बढ़ जाएगी। इससे इन उत्पादों के खराब होने की दर में कमी आएगी। किसानों को अपने उत्पाद पर अधिक लाभ मिलने के साथ ही उनको नुकसान भी कम होगा।

लैंड बैंक भी बनाएंगेः यमुना और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिंक प्वाइंट पर भी औद्योगिक गलियारा स्थापित होगा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे फिरोजाबाद व मैनपुरी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बाराबंकी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे चित्रकूट में जमीन ली जा रही है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जालौन में और दूसरा बांदा में विकसित होगा। औद्योगिक पार्कों के अलावा, राज्य सरकार ने राज्य में एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के किनारे भूमि बैंक विकसित करेगी। इसी तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे सात नये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से पांच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और दो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे होंगे। इसकी शुरुआत लखनऊ से होगी।

रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी इलेक्ट्रिक बसें, कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

पहले चरण में 250 ई बसों को चलाने की योजना है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2025 में होने वाले प्रयागराज कुंभ तक पांच हजार बसों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

परिवहन विशेष न्यूज

लखनऊ। प्रयागराज में वर्ष 2025 में होने वाले कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को रोडवेज की साधारण व एसी बसों के साथ ई बसों से भी सफर का मौका मिलेगा। रोडवेज प्रबंधन ने मेले तक पांच हजार नई इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य तय किया है। ये बसें एसी व नॉन एसी भी होंगी। इनकी खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उप्र. राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने बेड़े में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि पहले चरण में रोडवेज अपने बेड़े में 250 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार की फेम टू स्कीम के तहत मिलने वाले 40 फीसदी अनुदान के लिए पत्र भेजा गया है।

एमडी मासूम अली सरवर ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों को अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों को लखनऊ से जोड़ा जाएगा। प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) अजीत सिंह का कहना है कि रोडवेज की फ्लीट में कुंभ मेले से पहले ढाई सौ इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी। इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। बता दें, रोडवेज के बेड़े में करीब 12 हजार बसें हैं।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

पैदा होते ही कुड़ेदान में फ़ेंकी गई बच्ची आज है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कप्तान

महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक अनाथालय है, जिसे 'श्रीवास्तव अनाथालय' कहा जाता है। 13 अगस्त 1979 को शहर के एक अनजान कोने में एक लड़की का जन्म हुआ , बच्ची के माता पिता ने पैदा होते ही लड़की को एक अनाथालय के बाहर के कुड़े दान में फेंक दिया, अनाथालय प्रबंधक ने उस प्यारी सी बच्ची का नाम 'लैला' रखा।

उन दिनों हरेन और सू नाम का एक अमेरिकी जोड़ा भारत घूमने आया था। उनके परिवार में पहले से ही एक लड़की थी, भारत आने का उनका मकसद एक लड़के को गोद लेना था। वे एक सुन्दर लड़के की तलाश में इस आश्रम में आए। उन्हें एक लड़का नहीं मिला, लेकिन सू की नज़र लैला पर पड़ी और लड़की की चमकीली भूरी आँखों और मासूम चेहरे को देखकर उसे उससे प्यार हो गया।

कानूनी कार्रवाई करने के बाद, लड़की को गोद ले लिया गया, सू ने अपना नाम लैला से बदलकर 'लिज' कर लिया, वे वापस अमेरिका चले गए, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वे सिडनी में स्थायी रूप से बस गए।

पिता ने बेटी को क्रिकेट खेलना सिखाया, घर के पार्क से शुरू होकर गली के लड़के के साथ खेलने तक का यह सफर चला। क्रिकेट के प्रति उनका जुनून अपार था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। उसे एक अच्छा मौका मिला, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ गई। पहले वो बोलती थीं, फिर उनका बल्ला बोलने लगा और फिर उनके रिकॉर्ड बात करने लगे.

1997- न्यू-साउथ वेल्स द्वारा पहला मैच
2001- ऑस्ट्रेलिया का पहला ODI
2003- ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहला टेस्ट
2005- ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहला टी20

आठ टेस्ट मैच, 416 रन, 23 विकेट
125 वनडे, 2728 रन, 146 विकेट
54 टी-20, 769 रन, 60 विकेट

वनडे में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर

जब आईसीसी की रैंकिंग प्रणाली शुरू हुई तो वह दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर थे।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ! बहुत खूब !

ODI और T-20 - चार विश्व कप में भाग लिया।

2013 में उनकी टीम ने क्रिकेट विश्व कप जीता, उसके अगले दिन इस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने लीजा स्टालगर को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है।

इसलिए बेटी जरूर बचाओ

हिन्दू कौन है

क्या आप जानते हैं?

यदि नहीं जानते हैं, तो जो मैंने पढा, उसे आप भी पढ़ें और अगर, कोई त्रुटि हो तो अवगत अवश्य करवाएं।

हिन्दू शब्द की खोज

हीनं दुष्यति इति हिन्दूः से हुई है।

अर्थात: जो अज्ञनता और हीनता का त्याग करे उसे हिन्दू कहते हैं।

हिन्दू ' शब्द, करोड़ों वर्ष प्राचीन, संस्कृत शब्द से है!

यदि संस्कृत के इस शब्द का सन्धि विच्छेदन करें तो पायेंगे ....

हीन + दू = हीन भावना + (से) दूर

अर्थात : जो हीन भावना या दुर्भावना से दूर रहे , मुक्त रहे , वो हिन्दू है!

हमें बार - बार, सदा झूठ ही बतलाया जाता है कि हिन्दु शब्द मुगलों ने हमें दिया , जो " सिंधु " से " हिन्दू " हुआ । हिन्दू को गुमराह किया जा रहा है।

हिन्दू शब्द की वेद से ही उत्पत्ति है!

जानिए , कहाँ से आया हिन्दू शब्द और कैसे हुई इसकी उत्पत्ति ?

कुछ लोग यह कहते हैं कि हिन्दू शब्द सिंधु से बना है औऱ यह फारसी शब्द है । परंतु ऐसा कुछ नहीं है ! ये केवल झुठ फ़ैलाया जाता है। हमारे " वेदों " और " पुराणों " में हिन्दू शब्द का उल्लेख मिलता है । आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें हिन्दू शब्द कहाँ से मिला है!

"ऋग्वेद" के " ब्रहस्पति अग्यम " में हिन्दू शब्द का उल्लेख इस प्रकार आया हैं :-

" हिमालयं समारभ्य
यावद् इन्दुसरोवरं ।
तं देवनिर्मितं देशं
हिन्दुस्थानं प्रचक्षते ।"

अर्थात : हिमालय से इंदु सरोवर तक , देव निर्मित देश को हिंदुस्थान कहते हैं!

केवल " वेद " ही नहीं, बल्कि " शैव "ग्रन्थ में हिन्दू शब्द का उल्लेख इस प्रकार किया गया हैं :-

हीनं च दूष्यतेव् हिन्दुरित्युच्च ते प्रिये।

अर्थात :- जो अज्ञनता और हीनता का त्याग करे उसे हिन्दू कहते हैं!

इससे मिलता जुलता लगभग यही श्लोक " कल्पद्रुम " में भी दोहराया गया है:

हीनं दुष्यति इति हिन्दूः ।

अर्थात : जो अज्ञनता और हीनता का त्याग करे,उसे हिन्दू कहते हैं।

" पारिजात हरण " में हिन्दु को कुछ इस प्रकार कहा गया है :-

हिनस्ति तपसा पापां
दैहिकां दुष्टं ।
हेतिभिः श्त्रुवर्गं च
स हिन्दुर्भिधियते ।"

अर्थात :- जो अपने तप से शत्रुओं का , दुष्टों का , और पाप का नाश कर देता है , वही हिन्दू है !

" माधव दिग्विजय " में भी हिन्दू शब्द को कुछ इस प्रकार उल्लेखित किया गया है :-

"ओंकारमन्त्रमूलाढ्य
पुनर्जन्म द्रढ़ाश्य: ।
गौभक्तो भारत:
गरुर्हिन्दुर्हिंसन दूषकः ।"

अर्थात : वो जो " ओमकार " को ईश्वरीय धुन माने , कर्मों पर विश्वास करे , गौ-पालक रहे , तथा बुराइयों को दूर रखे, वो हिन्दू है!

केवल इतना ही नहीं , हमारे "ऋगवेद" (8:2:41) में हिन्दू नाम के बहुत ही पराक्रमी और दानी राजा का वर्णन मिलता है , जिन्होंने 46,000 गौमाता दान में दी थी ! और "ऋग्वेद मंडल" में भी उनका वर्णन मिलता है।

बुराइयों को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहने वाले , सनातन धर्म के पोषक व पालन करने वाले हिन्दू हैं ।

गर्व से कहो हम हिंदू हैं

स्कूल जाता आपका लाडला न हो जाए Dengue का शिकार!

आजकल डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, बदलते मौसम के चलते कई लोग इस बीमरी की चपेट में आ रहे हैं। बच्चे भी इस अछूते नहीं है। उनमें भी इसके कई सारे लक्षण और प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाता है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये सावधानियों के साथ बच्चे जितना हो सके डेंगू के बुखार से दूर रहेंगे और मच्छरों उन्हें अपना शिकार नहीं बना पाएंगे....

लक्षण पहचानें

- तेज बुखार
- उल्टी
-आंखों के पीछे दर्द
- कमजोरी और स्किन पर लाल चकत्ते

ऐसे करें बच्चों का डेंगू से बचाव

मच्छर भगाने वाली क्रीम का करें इस्तेमाल

बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अच्छी तरह से मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं। बच्चे के बैग में भी क्रीम रखें। वहीं आप बच्चों को आसानी से लगनी वाली रोल ऑन या स्प्रे वाले रेपेलेंट भी भेज सकते हैं।

अंदर रहें

बच्चे ज्यादातर शरारती स्वभाव के होते हैं। उन्हें स्कूल में किन जगहों पर खेलना चाहिए और कहां नहीं ये बताएं। पानी भरी हुई जगह और घास वगैरह से बच्चों को दूर रहने के लिए कहें। इन जगहों पर ही मच्छर सबसे ज्यादा पनपते हैं।

डाइट में बदलाव

बच्चों की डाइट में उन फूड्स को शामिल करें जो उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। दही, हल्दी, अदरक, लहसुन, पालक, बादाम और खट्टे फल आदि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली डाइट का हिस्सा बनाए जा सकते हैं।

ढके कपड़े

बच्चों को आधी बाजू के कपड़े पहनाने की जगह पूरी बाजू की स्कूल ड्रेस पहनाकर भेजें। स्कर्ट के नीचे स्टॉकिंग या पाजामी पहनाई जा सकती है। गर्दन और हाथ-पैर जहां से भी खुले रहें वहां मच्छर मारने की दवा लगाकर भेजें।

बच्चा नहीं सुनता है आपकी बात तो इन 5 स्मार्ट पैरेंटिंग टिप्स से करें उन्हें हैंडल

आजकल बच्चे काफी हद तक जिद्दी हो गए हैं। कई बारे पैरेंट्स उन्हें काफी बार रोकते- टोकते हैं। लेकिन जब बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो पैरेंट्स उन्हें कुछ कहना ही बंद कर देते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है क्योंकि आपका बच्चा आपसे ही सीखता है, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को डांटने के बजाए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करें ताकि बच्चे आपकी बातों को सुने। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिद्दी बच्चा आपकी सुने तो ये स्मार्ट पेरेंटिंग टिप्स अपनाएं..

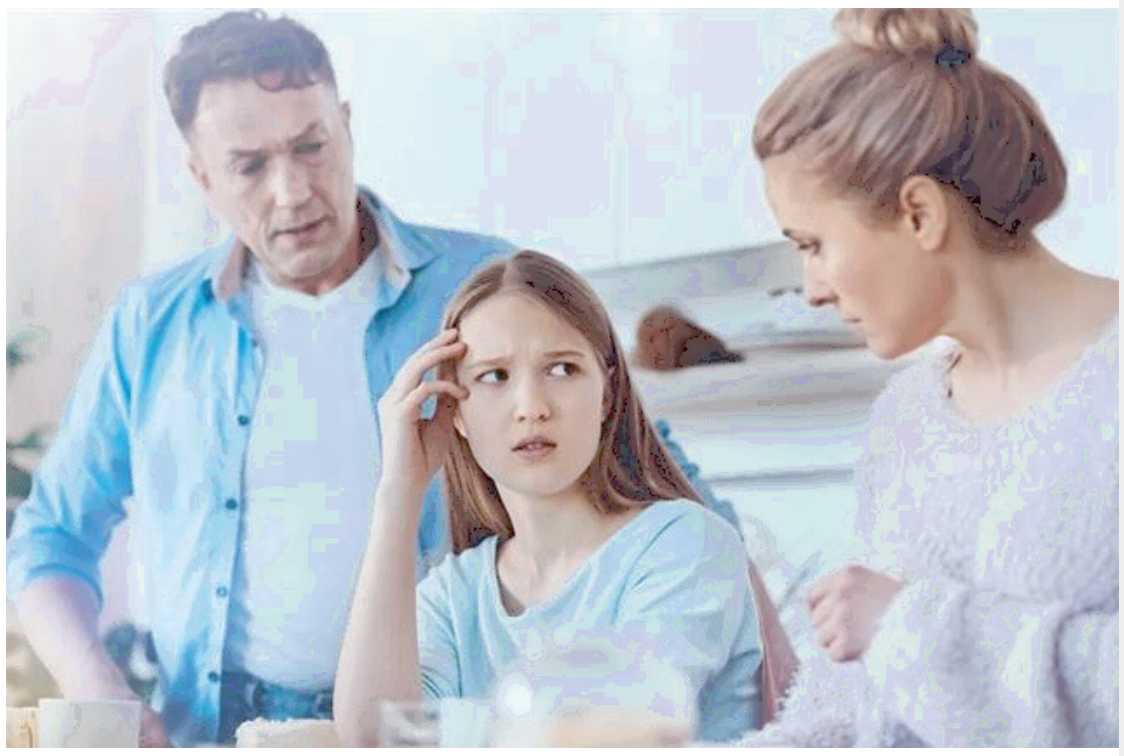

सोच- समझकर करें शब्दों का चयन

बच्चों को डांटने और ये बोलने के बजाए कि 'तुम सच में बहुत ही गंदे बच्चे हो', आप ये कह सकते हैं कि राहुल अब तुम बड़े हो रहे हो'। गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से बच्चे के मन को ठेस पहुंचती हैं और उनको लगता है कि वो कोई काम का नहीं है, साथ में ही उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों के साथ पॉजिटिव रहें और डांटने के बजाए समझाएं। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपनी बातों पर गौर करेगा।

तेज आवाज में ना करें बात

अपने बच्चे से ऊंची आवाज में बात न करें। बार- बार इसी तरह से बात करने में हो सकता है वो अंदर से डर जाएं। इसलिए अगर बच्चा नाराज होकर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो पहले तो उसका गुस्सा शांत करें। बाद में उनसे प्यार से पूछें। इससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा नहीं होगा और वो आपकी बात पर ज्यादा ध्यान से सुनेंगे।

प्यार से समझाएं

बच्चा आपकी तभी सुनेगा और तभी आपके साथ कोऑपरेट करेगा, जब आप उन्हें सही तरीके और विकल्प के बारे में बताएंगी। ऐसे में विकल्प के साथ उठने-बैठने का तरीका भी बताना जरूरी है जैसे- 'जब तुम तैयार हो जाओ, तो पापा के साथ बाहर जा सकते हो₹, 'ब्लू या ब्लैक ट्राउजर में से कौन सा पहनना चाहते हो₹, 'जब होमवर्क पूरा कर लो तो टीवी देख सकते हो₹ आदि। ये छोटी-छोटी बातें आपके प्रति उनके मन में विश्वास पैदा करेगा। ऐसे में वे आपकी जरूर सुनेंगे। अपनी समस्याओं को हल करने में भी उनकी मदद लें।

शिष्टाचार का पाठ पढ़ाएं

बच्चे को बेसिक शिष्टाचार की बातें जैसे प्लीज, थैंक यू, यू आर वेलकम का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, उन्हें बताएं। आप खुद भी इन शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, आप जो भी बोलती हैं, बच्चे वही सीखते और आपस में दोस्तों के साथ कहते हैं।

स्वीकृति दिखाएं

बच्चे को यह जताएं की वे जैसे हैं उसी रूप में आप उनसे प्यार करती हैं। फिर देखिए कैसे वे खुद ही आकर अपनी भावनाओं, मन की बात आपसे शेयर करेंगे। इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा कि जब भी वे किसी मुसीबत में होंहे आप उनके लिए हमेशा खड़ी होंगी। जब बच्चा आपसे कुछ शेयर करता है तो उसकी पूरी बात सुनें। बीच में न बोल पड़ें। यदि वह कहते है कि छत पर दोस्तों के साथ खोल रहा था तो अचानक यह लेक्चर न देने लगें कि छत पर क्यों गए, गिर जाते तो? ऐसे में वह दोबारा आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेगा। पहले ठंडे दिमाग से उसकी पूरी बात सुनें, उसके बाद ही प्यार से समझाएं कि छत पर खेलना खतरनाक क्यों है।

होटल फोर लीफ में पूजा शर्मा और मनिंदर कौर की अध्यक्षता में तीज का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया

(साहिल बेरी)

अमृतसर। होटल फोर लीफ में पूजा शर्मा और मनिंदर कौर की अध्यक्षता में तीज का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जिसमें रैंप वॉक, डांस, गिद्दा, मिस तीज बेस्ट टाइटल, तंबोला का प्रोग्राम रखा गया, इस प्रोग्राम में मुख्यमन मैडम (मैडम शमा जुनेजा डिज़ाइनर हब) (बीनू कपूर मेकअप आर्टिस्ट) (सुलेखा मेहरा टैरोट कार्ड रीडर) (सोनी सलूजा राइजिंग सन दुपट्टा) कार्यक्रम में मंच का संचालन प्रसिद्ध एंकर मीनाक्षी वैद्य ने बखूबी निभाया। फूलों से किए श्रृंगार के साथ सज धज कर आई महिलाओं ने कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, इस मौके एंकर मीनाक्षी वैद्य ने कहा कि तीज का त्योहार हमें अपने संस्कृति के साथ जोड़ता है और इस त्यौहार का महिलाओं को बहुत देर से इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में हरियाली का आरंभ करने वाले त्योहार हरियाली तीज से ही त्योहारों का आगमन होता है जो होली तक चलता है। मीनाक्षी वैद्य ने सभी को तीज की शुभकामनाएं दी। इस मौके मीनाक्षी वैद्य, सोनिया, ज्योति, मोनिका, और भी महिलाओं ने इस प्रोग्राम का आनंद लिया।

बारिश से जलमग्न हुईं दिल्ली-NCR की सड़कें
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर लगा भारी जाम

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार तड़के हुई तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। बारिश के बाद से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सूचना के अनुसार बारिश के कारण इलाके में जलभराव के कारण दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भारी जाम लगाया है।

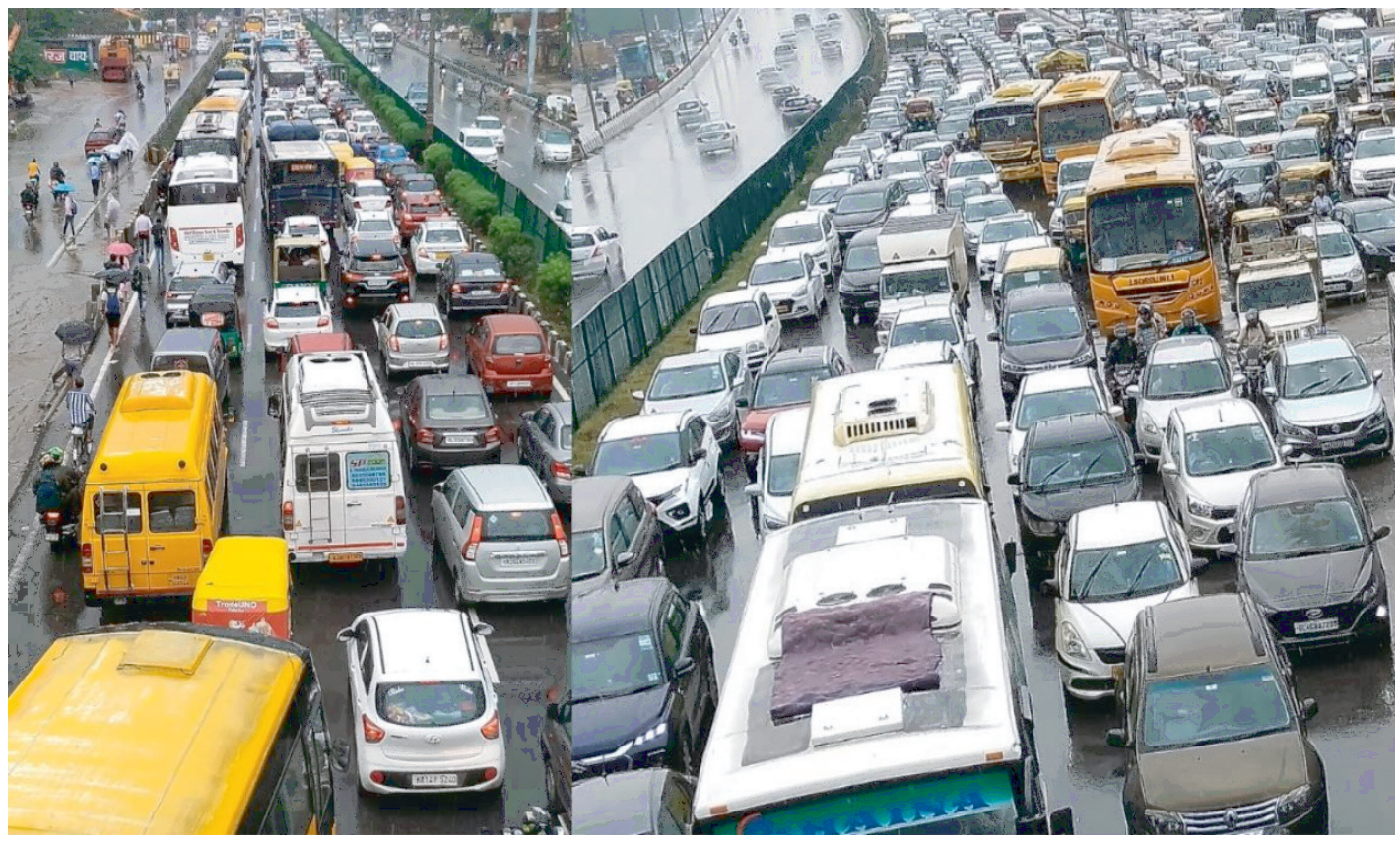

नईदिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में शनिवार तड़के हुई तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। बारिश के बाद से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है।

सूचना के अनुसार, बारिश के कारण इलाके में जलभराव के कारण दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भारी जाम लगाया है।

वहीं, हरियाणा में भी भारी बारिश के कारण गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को पानी से होकर गुजरना पड रहा है।

साफ हुई दिल्ली की हवा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह 8 बजे 151 की रीडिंग के साथ 'मध्यम' श्रेणी में था।

शून्य और 50 के बीच एक AQI को 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।

दो महीने से भाव खाते टमाटर पर धोबी पछाड 40

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। पिछले दो महीने से भाव खाते टमाटर की कीमतों पर 40 रू. के धोबी पछाड़ ने औंधे मुंह गिरा दिया है। टमाटर की सेब = बेशकीमती लाली से बेहाल आम लोगो को अब राहत मिलती दिखाई दे रही है। टमाटर रेट की ऐंठ को एक तरफ नेपाल से टमाटर का आयात शुरू हो गया है। वहीं टमाटर की बची खुची ऐंठ को देश के अन्य उत्पादक क्षेत्रों से भी टमाटर की भारी भरकम आवक भी शुरू हो रही है। इसके अलावा सरकार एनसीसीएफ और नैफेड के माध्यम से कुछ खास दुकानों पर सस्ती दरों पर टमाटर को सडकों /मंडियों में उतार दिया है। यहां भी टमाटर की कीमत में कमी कर दी गई है। अब यहां भी तय कीमत से 10 रूपये और कम पर टमाटर बेचा जा रहा है। इससे स्टॉकिस्टों और कालाबाजारियों में भगदड मच गयी है। उन्होने भी टमाटरों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। टमाटर की नई दरें रविवार 20 अगस्त से लागू कर दी जाएगी। 20 अगस्त से टमाटर की थोक और खुदरा कीमतों में गिरावट के बीच सहकारी संस्थान एनसीसीएफ और नैफेड 20 अगस्त से 40/- रूपये प्रति किलो की दर से टमाटर बेचेंगे।

महाठग सुकेश का एक और पत्र: सीएम केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर ये आरोप लगा एलजी को भेजी शिकायत

दिल्ली की मंडोली जेल में ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बंद सुकेश चंद्रशेखकर ने अपने वकील के जरिए से यह पत्र राज्यपाल के कार्यालय को भेजा है। हालांकि, इस बार पत्र को मीडिया के साथ साझा नहीं किया है। वकील की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए संक्षिप्त जानकारी दी है।

नई दिल्ली। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्र शेखर ने एक बार फिर से राज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जड़े हैं। महाठग सुकेश ने सीएम केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर मेडिकल कंपनी से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही जांच की मांग भी की है। सुकेश चंद्रशेखर ने तीन पेज का पत्र राज्यपाल को भेजा है। ठग सुकेश ने आरोप लगाया है कि मेडिकल कंपनी के मालिक आम आदमी पार्टी के साथ बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इस कंपनी को कई कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। सुकेश ने पत्र में अपने आरोपों के समर्थन में कुछ डिटेल भी राज्यपाल को भेजी है।

दिल्ली की मंडोली जेल में ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बंद सुकेश चंद्रशेखकर ने अपने वकील के जरिए से यह पत्र राज्यपाल के कार्यालय को भेजा है। हालांकि, इस बार पत्र को मीडिया के साथ साझा नहीं किया है। वकील की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए संक्षिप्त जानकारी दी है। वकील ने अनुरोध किया है कि न्याय, समानता और अच्छे विवेक के हित में इस संबंध में जल्द से जल्द न्यायसंगत कार्रवाई शुरू की जाए।

इससे पहले भी सुकेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर कई चौंकाने वाले दावे कर चुका है। सुकेश ने कहा था कि आप के राष्ट्रीय संजोयक ने उसे अपनी पार्टी के लिए फंड जुटाने का कार्य दिया था।

स्पेशल सेल ने किया ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़
40 करोड़ कीमत की 56KG से ज्यादा अफीम बरामद

परिवहन विशेष न्यूज

पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर अंतरराज्यीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। आरोपितों के पास से टीम को 56 .55 किलोग्राम अफीम एक ट्रक कई मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। बरामद हुई अफीम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 40 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी।

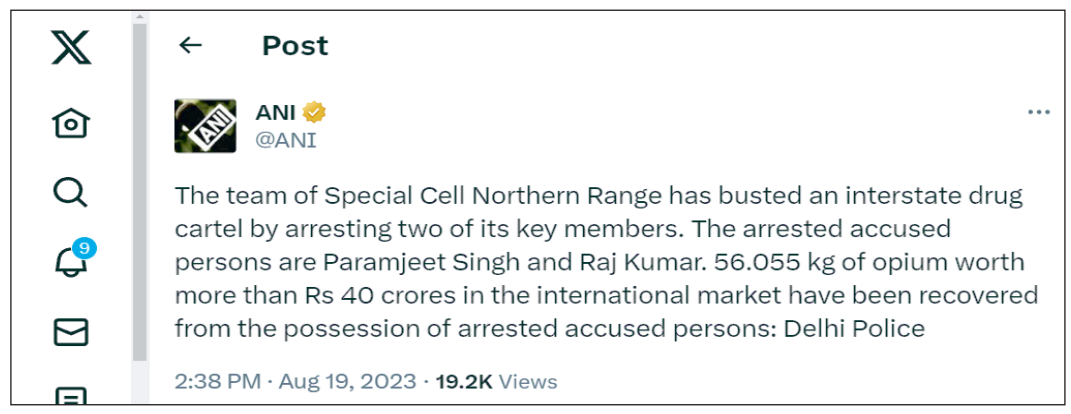

Post
ANI
@ANI
The team of Special Cell Northern Range has busted an interstate drug cartel by arresting two of its key members. The arrested accused persons are Paramjeet Singh and Raj Kumar. 56.055 kg of opium worth more than Rs 40 crores in the international market have been recovered from the possession of arrested accused persons: Delhi Police
2:38 PM · Aug 19, 2023 · 19.2K Views

नई दिल्ली। पुलिस की नॉर्दर्न रेंज की स्पेशल सेल टीम ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर अंतरराज्यीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। टीम ने आरोपितों के पास से 40 करोड़ रुपये की कीमत से ज्यादा की अफीम, एक ट्रक और कई मोबाइल बरामद की हैं।

पुलिस ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करने के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्पेशल सेल की टीम ने एनआर और एसटीएफ ने अंतरराज्यीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ कर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान जम्मू-कश्मीर के निवासी परमजीत सिंह और राजकुमार के रूप में हुई है।

ट्रक सहित मोबाइल भी बरामद

आरोपितों के पास से टीम को 56.55 किलोग्राम अफीम जिसकी एक ट्रक, कई मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। वहीं, आरोपितों के पास से बरामद हुई अफीम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस टीम ने ऑपरेशन के बारे में बताते हुए कहा कि 20 जुलाई, 2023 को इंस्पेक्टर विवेक पाठक के नेतृत्व में बनी टीम को जम्मू-कश्मीर के निवासी परमजीत और राजकुमार के बारे में विशेष जानकारी मिली, जो असम बोकाजन के निवासी निर्मल के निर्देश पर मणिपुर से अफीम की सप्लाई खरीद कर ट्रक से शनिवार सुबह दिल्ली के मंगोलपुर औद्योगिक क्षेत्र आएंगे, जहां से वह सुल्तानपुरी निवासी संजीत को आपूर्ति के लिए भारी मात्रा में अफीम देंगे।

इसके बाद टीम का गठन कर आरोपितों को घटनास्थल पर पहुंचने पर पकड़ लिया और तलाशी के दौरान परमजीत सिंह के पास से 5.195 किलोग्राम और 50.860 किलोग्राम अफीम बरामद की है। आरोपितों के खिलाफ पीएस स्पेशल सेल में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी।

कार का 'Sunroof' खोलकर छत पर लेटकर किया स्टंट, पुलिस ने काटा इतने हजार का चालान

नोएडा में स्टंटबाजी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। सोशल मीडिया पर 19 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक सफेद रंग की कार की छत पर लेटकर स्टंट कर रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए कार का 26 हजार रुपये का चालान किया गया है।

दिल्ली से सटे नोएडा में स्टंटबाजी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कारों में सनरूफ खोलकर लोग आए दिन स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है। एक कार का सनरूफ खोलकर एक युवक स्टंट दिखा रहा है। नोएडा के सेक्टर 18 में एक शख्स कार का सनरूफ खोलकर स्टंट करता हुआ दिख रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने कार मालिक का 26,000 रुपये का चालान किया है। जानकारी के अनुसार, बुधवार को सोशल मीडिया पर 19 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक सफेद रंग की कार का सनरूफ खोलकर उसकी छत पर लेटकर स्टंट कर रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए कार का 26 हजार रुपये का चालान किया गया है। वहीं आरोपियों की पहचान की जा रही है। वायरल वीडियो थाना 24 क्षेत्र का बताया जा रहा है।

शराब के नशे में बदमाशों ने राहगीरों पर चलाए चाकू, एक की मौत और दो घायल; लूट के लिए की ये वारदात

बदमाशों की पहचान कपिल चौधरी, सोहेल और समीर के रूप में हुई है। इनमें से समीर फिलहाल फरार है। जिसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

नईदिल्ली। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला वेलकम इलाके का है। यहां बदमाशों ने चाकू से लूट के इरादे से तीन लोगों पर जानलेवा हमला किया जिसमें से एक की मौत हो गई और दो घायल हैं। घायलों ने भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, चाकूबाजी की तीनों घटना जनता मजदूर कॉलोनी की बताई जा रही हैं। पहली घटना में बदमाशों ने शेर मोहम्मद के पेट में चाकू मारा। उसने एक घर के अंदर छिपकर खुद की जान बचाई। दूसरी घटना कॉलोनी के मकान नंबर 569 की है, जहां गुफरान की पीठ में चाकू मारा गया। गुफरान का खून काफी बह गया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई। बदमाशों ने उसका मोबाइल फोन लूट लिया। वह गांधीनगर में एक जींस की फैक्ट्री में दर्जी का काम करता था। वहीं, तीसरी घटना इसी कॉलोनी की है, जहां बदमाशों ने सारी कुमार (22) की गर्दन पर चाकू मार दिया।

बदमाशों की पहचान कपिल चौधरी, सोहेल और समीर के रूप में हुई है। इनमें से समीर फिलहाल फरार है। जिसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कपिल, सोहेल और समीर शराब पी रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों को लूटने का फैसला किया। उनके पास बड़े चाकू थे, जो उन्होंने हाल ही में बल्लीमारान इलाके से खरीदे थे। उन्होंने तीन लोगों को चाकू मारा लेकिन उनमें से केवल एक को ही लूटने में सफल रहे, जिसकी चोटों के कारण मौत हो गई। तीनों लड़के इलाके के जाने-माने बदमाश हैं और उनमें से दो का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है।

राजस्थान में जिन जगहों पर शूटरों को प्रशिक्षण दिया गया, वहां पर स्पेशल सेल की टीम ने निरीक्षण कर पाच से छह बदमाशों को गिरफ्तार भी कर चुकी है।

मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा: राजस्थान में रची गई थी साजिश, शूटरों ने ली थी हथियार चलाने की ट्रेनिंग

पंजाबी गायब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने वाले शूटरों को राजस्थान में विदेशी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही मूसेवाला की हत्या की साजिश भी हरियाणा बॉर्डर से सटे राजस्थान के एक गांव में रची गई थी। हत्या में इस्तेमाल हथियार पाकिस्तान से आए थे। इन हथियारों को पंजाब से राजस्थान लाया गया।

नई दिल्ली। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने वाले शूटरों को राजस्थान में विदेशी हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। शूटरों को वहीं पर ही मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने की पूरी तैयारी कराई गई।

राजस्थान के गांव में रुके थे शूटर

शूटरों को हरियाणा बार्डर से सटे राजस्थान के गांवों में ठहराया गया। वहां बने फार्महाउस, खेत आदि में स्नाइपर, पिस्टल, राइफल और हैंड ग्रेनेट जैसे हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटरों को सबसे पहले गिरफ्तार किया था।

पूछताछ में पता चला कि राजस्थान के गैंगस्टरों ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटरों को न केवल प्रशिक्षण दिया था, बल्कि उन्हें हत्या से पहले और बाद में छिपने के लिए शरण भी दिया था। राजस्थान में जिन जगहों पर शूटरों को प्रशिक्षण दिया गया, वहां पर स्पेशल सेल की टीम ने निरीक्षण कर पाच से छह बदमाशों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। यह सभी बदमाश राजस्थान के ही रहने वाले हैं।

पाकिस्तान से आए थे हथियार

स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हथियार पाकिस्तान से आए थे। इन हथियारों को पंजाब से राजस्थान लाया गया। प्रशिक्षण के बाद इन हथियारों को राजस्थान से हरियाणा फिर पंजाब भेजा गया। इस मामले में स्पेशल सेल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है जिसमें उक्त तथ्यों को मजबूती से शामिल किया गया है।

UP सरकार की छवि खराब करने की कोशिश

सूत्रों का कहना है कि हाल ही में मूसेवाला हत्याकांड में शामिल लारेंस बिश्नोई के शूटरों की कुछ तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई है। उसे मूसेवाला हत्याकांड से पहले का बताया जा रहा है। उक्त तस्वीरें लखनऊ और अयोध्या की हैं। स्पेशल सेल के सूत्रों ने बताया कि शूटरों की कुछ तस्वीरें लखनऊ और अयोध्या क्षेत्र की हो सकती हैं, लेकिन काफी समय पहले की हैं, जब मूसेवाला हत्याकांड की साजिश नहीं रची गई थी।

यह भी दावा किया जा रहा है कि अयोध्या के माफिया विकास सिंह के फार्महाउस में शूटरों को प्रशिक्षण दिया गया। यह पूरी तरह से तथ्यहीन बात है। विकास सिंह पर पूर्व में मुकदमें दर्ज हैं, यह भी हो सकता है कि लारेंस गिरोह से उसका संपर्क हो। स्पेशल सेल की जांच में अभी तक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड सिलसिले में शूटरों का यूपी के अयोध्या से कोई कनेक्शन और विकास सिंह की कोई भूमिका सामने नहीं आई है।

सूत्रों का कहना है कि राजस्थान के कुछ गैंगस्टर विकास सिंह के जरिये यूपी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अपुष्ट और आधारहीन तथ्यों को प्रसारित किया जा रहा है। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मनसा जिले में सरेआम हत्या कर दी गई थी। लारेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े शूटरों ने उनकी थार गाड़ी को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस 30 से अधिक आरोपितों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है।

क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना, 5 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को लोन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। वहीं अब कैबिनेट ने योजना के लिए 13 हजार करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए हैं। इसमें पहली बार 18 परंपरागत व्यवसायों से जुड़े परिवारों को कवर किया जाएगा। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों व शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर 'पीएम विश्वकर्मा योजना' लॉन्च की जाएगी।

दरअसल, केंद्र सरकार ने परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देने के लिए 'पीएम विश्वकर्मा' योजना को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में इस योजना का उल्लेख किया था। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को इसे मंजूरी प्रदान की। योजना के तहत 18 परंपरागत व्यवसायों में प्रमुख रूप से नौका निर्माता, लोहार, टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, राजमिस्त्री, बुनकर, परंपरागत खिलौना निर्माता, नाई, धोबी, दर्जी और जाल निर्माता शामिल हैं।

विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी दी जाएगी

योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत इन कार्यों से जुड़े लोगों के कौशल विकास, बाजार पहुंच और आर्थिक सहयोग पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्हें बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। डिजिटल लेनदेन में प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

क्या होगा लाभ

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक आपाधापी में पीछे छूट गए गुरु-शिष्य परंपरा के तहत चले आ रहे इन व्यवसायों को सरकार मदद प्रदान करेगी। इसके तहत 30 लाख परिवारों के किसी एक व्यक्ति को योजना से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत उन लोगों को 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कौशल विकास सामग्री खरीद में भी मदद दी जाएगी। पहले वर्ष में पांच लाख परिवारों को कवर किया जाएगा और वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2028 तक पांच वर्षों में कुल 30 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा।

इन व्यवसाय वालों को किया गया है शामिल

(1) बढ़ई (सुथार); (2) नाव निर्माता; (3) अस्त्र बनाने वाला; (4) लोहार (5) हथौड़ा और टूल किट निर्माता; (6) ताला बनाने वाला; (7) गोल्डस्मिथ (सुनार); (8) कुम्हार; (9) मूर्तिकार (पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला); (10) मोची (चर्मकार)/जूता कारीगर; (11) मेसन (राजमिस्त्री); (12) टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/जूट बुनकर; (13) गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक); (14) नाई; (15) माला बनाने वाला; (16) धोबी; (17) दर्जी और (18) मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला शामिल हैं।

रिकॉर्ड मुनाफे से उत्साहित एसबीआई देशभर में खोलेगा 300 नई शाखाएं

परिवहन विशेष न्यूज

सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चालू वित्त वर्ष में देशभर में 300 नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है। बैंक के इस कदम से संभवतः ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने में मदद मिलेगी।

देशभर में एसबीआई की कितनी शाखाएं ?

वर्तमान में देशभर में SBI की 22 हजार 405 शाखाएं और 235 विदेशी शाखाएं और कार्यालय मौजूद हैं। बैंक देश के अलग-अलग हिस्सों में 300 नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग के साथ भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर लेकर आया है।

एसबीआई को मिला रिकॉर्ड मुनाफा

एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने इस संबंध में कहा है कि बैंक अपने डिजिटल परिचालन का विस्तार करना चाह रहा है और जब भौतिक (बैंकिंग) की बात आती है, तो बैंक चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 300 शाखाएं खोलने का प्लान बना रहा है। बैंक अधिक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट रखने पर भी विचार कर रहा है। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में गिरावट, उच्च ऋण वृद्धि और उच्च ब्याज दर के कारण भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपना अब तक का सबसे अधिक 16 हजार 884 करोड़ रुपये का तिमाही लाभ दर्ज किया है। एक साल पहले की समान तिमाही में इसका शुद्ध लाभ 6 हजार 68 करोड़ रुपये था।

एसबीआई के बारे में...

उल्लेखनीय है कि 'भारतीय स्टेट बैंक' या 'स्टेटबैंकऑफ़इण्डिया' बैंकिंग जगत का एक विख्यात नाम है। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सरकारी बैंक है जिसकी शाखा भारत के साथ-साथ अन्य देशों में मौजूद है। इसी के साथ एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की सांविधिक निकाय है। एसबीआई का प्रयोग हम धन संचय और पैसो का लेन-देन करने के लिए करते हैं।SBI 48 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा कर रहा प्रदान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 200 वर्षों से अधिक की समृद्ध विरासत और पीढ़ियों से भारतीयों द्वारा सबसे भरोसेमंद बैंक के रूप में एसबीआई को मान्यता मिली है।

29 देशों में 235 कार्यालय

एसबीआई, एक चौथाई बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा भारतीय बैंक, 22,405 से अधिक शाखाओं, 65,627 एटीएम व एडीडब्ल्यूएम, 76,089 बीसी आउटलेट के अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से 48 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। इसमें नवाचार और ग्राहक केंद्रितता पर निरंतर ध्यान दिया जाता है, जो कि बैंक के मूल मूल्य-सेवा, पारदर्शिता, नैतिकता, विनम्रता और स्थिरता से उत्पन्न होता है।

बैंक ने अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों यानी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई कार्ड इत्यादि के माध्यम से व्यवसायों को सफलतापूर्वक विविधीकृत किया है। इसने विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति को विस्तार दिया है और यह 29 विदेशी देशों में अपने 235 कार्यालयों के माध्यम से समय क्षेत्रों में काम करता है। समय के साथ बढ़ते हुए, एसबीआई ने भारत में बैंकिंग को फिर से परिभाषित करना जारी रखा है, क्योंकि इसका लक्ष्य जिम्मेदार और टिकाऊ बैंकिंग समाधान पेश करना है।

सिम डिलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, 67 हजार डीलर हुए ब्लैकलिस्ट

परिवहन विशेष न्यूज

मोबाइल फोन सिम के जरिए धोखाधड़ी और मिस यूज आज के दौर में सामान्य बात हो गई है। लेकिन अब इन धोखाधड़ी पर लगाम लग रही है। केंद्र सरकार ने सिम डीलरों के लिए नया नियम बनाया है। जिसके तहत अब देश में मोबाइल फोन के सिम विक्रेताओं का अब पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा, जिसमें उनकी बायोमेट्रिक जानकारी भी शामिल है। अब बड़ी संख्या में बिजनेस कनेक्शन लेने वाले कारोबारियों को सिम देते समय सम्बन्धित कर्मचारी का केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।

बड़ी संख्या में सिम खरीद पर रोक

केन्द्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्वनी वैष्णव ने टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़े दो रिफॉर्म की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन रिफॉर्म का मकसद केवल उपयोगकर्ता को साइबर धोखाधड़ी से बचाना है। उन्होंने कहा कि सिम बेचने वाले को अब गलत तरीके से इसे बेचने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके लिए उसका पुलिस और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा और बड़ी संख्या में सिम खरीद पर रोक होगी। इसके स्थान पर बिजनेस कनेक्शन दिए जायेंगे। बिजनेस कनेक्शन के लिए एक प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। यह बिजनेस कनेक्शन पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।

केंद्र सरकार ने लिया एक्शन

केंद्रीय मंत्री ने संचार पोर्टल के माध्यम से हासिल की गई उपलब्धियों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संचार पोर्टल के जरिए 52 लाख फर्जी कनेक्शन खत्म किए गए हैं। 67 हजार डीलर ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। साइबर फ्रॉड से जुड़ी 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 17 हजार मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए गए हैं। 67 हजार व्हाट्सएप ब्लॉक किए गए हैं। एक लाख पेमेंट अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। तीन लाख चोरी के मोबाइल उनके मालिकों तक पहुंचाए गए हैं। एक आधार पर सिम लेने की संख्या को अभी भी नौ बनाए रखा गया है।

पुलिस वेरिफिकेशन और KYC के लिए मिलेगा समय

उन्होंने बताया कि डिजिटल केवाईसी जल्द ही जरूरी कर दिया जाएगा। सिम कार्ड देते समय आधार कार्ड के क्यूआर कोड को सत्यापित करना जरूरी होगा। इससे फोटो शॉप के दस्तावेज की हेरफेर खत्म होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि 10 लाख सिम डीलर को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों स्थिति पर पहली खुली बैठक

परिवहन विशेष न्यूज

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) 17 अगस्त को उत्तर कोरिया की गंभीर मानवाधिकार स्थिति पर न्यूयॉर्क में पहली खुली बैठक कर रहा हैं । इस बैठक में यूएनएससी उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के हनन पर चर्चा करेगी। 2017 के बाद से यह इस मुद्दे पर 15 सदस्यीय परिषद की यह पहली औपचारिक सार्वजनिक बैठक हैं।

दरअसल, कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने संवाददाताओं से कहा था कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क और एकांतप्रिय पूर्वोत्तर एशिया देश में मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अन्वेषक एलिजाबेथ सैल्मन 17 अगस्त की बैठक में परिषद के सदस्यों को जानकारी देंगे।

थॉमस-ग्रीनफील्ड ने यह भी कहा था कि उत्तर कोरिया के मानवाधिकारों का हनन और उल्लंघन उसके सामूहिक विनाश के गैरकानूनी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद को रभयावहता, दुर्व्यवहार और अपराधों पर ध्यान देना चाहिएर।

इस महीने परिषद के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस-ग्रीनफील्ड ने अल्बानिया, जापान और दक्षिण कोरिया के राजदूतों के साथ इस खबर की घोषणा की। थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा कि परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क और डीपीआरके में मानवाधिकार की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत एलिजाबेथ सैल्मन द्वारा जानकारी दी जाएगी।

पहले परमाणु परीक्षण के बाद से लगे हैं प्रतिबंध

सुरक्षा परिषद ने 2006 में उत्तर कोरिया के पहले परमाणु परीक्षण विस्फोट के बाद प्रतिबंध लगा दिए थे। उस समय जो प्रस्ताव पारित किया था उसमें कहा गया था कि उत्तर कोरिया अपना परमाणु हथियार, और बैलेस्टिक मिसाइलें नष्ट करे। इसके आधार पर सभी देशों पर यह रोक लग गई है कि वे उत्तर कोरिया को किसी भी गैरपारंपरिक हथियार निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध न करवाएं और टैंक, मिसाइल और हेलीकॉप्टर जैसे बड़े उपकरण न बेचे। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े व्यक्तियों और व्यावसायिक संगठनों के खाते सील कर दिए जाएं। इसके बाद उत्तर कोरिया जा रहे जहाज़ों की जांच की जा सकेगी।

उत्तर कोरिया ने मानवीय स्थिति के लिए प्रतिबंधों को ठहराया जिम्मेदार

उत्तर कोरिया ने इन दुर्व्यवहार के आरोपों को बार-बार खारिज किया है और गंभीर मानवीय स्थिति के लिए केवल प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया है। 2006 से यह अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु कार्यक्रमों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अधीन है, लेकिन सहायता में छूट भी है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बड़ी घोषणा, प्रदेशभर में 450 अनधिकृत कॉलोनियों होंगी नियमित

पहली बार राज्य सरकार नगर निगम सीमा से बाहर स्थित कॉलोनियों को भी करेगी नियमित- मनोहर लाल

1833 और कॉलोनियों को नियमित करने पर विचार कर रही सरकार, जल्द ही इसके लिए योजना बनाएंगे- मुख्यमंत्री

परिवहन विशेष न्यूज

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए प्रदेशभर में 450 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में सरकार द्वारा लिया गया यह परिवर्तनकारी निर्णय शहरी विकास, नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने और संगठित व सुव्यवस्थित शहरीकरण को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने आज यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इन 450 कॉलोनियों में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 239 कालोनियां तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 211 कालोनियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज नियमित की गई कालोनियों में पहली बार उन अनधिकृत कालोनियों को भी नियमित किया गया है, जो पालिका क्षेत्रों के बाहर स्थित हैं। ये नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अन्तर्गत आती हैं।

मनोहर लाल ने कहा कि इससे पहले वर्ष 2014 से 2022 तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अन्तर्गत आने वाली 685 कालोनियां नियमित की गई थीं। इस प्रकार, आज नियमित होने वाली कॉलोनियों को नियमित करने से वर्ष 2014 से अब तक कुल 1135 अनधिकृत कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी।

सरकार 1856 और कॉलोनियों को नियमित करने पर कर रही विचार कर रही

मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों के संबंध में भविष्य की योजना को साझा करते हुए बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 1856 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना विचाराधीन है। इनमें 727 कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग तथा 1129 कॉलोनियां शहरी स्थानीय विभाग के अंतर्गत आती हैं। इन कॉलोनियों में मापदण्ड पूरे होने पर इन्हें भी नियमित किया जाएगा। यह राज्य के शहरी नियोजन और विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नियमों को आसान बनाया।

मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 874 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था। हालाँकि, वर्तमान सरकार ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियमितीकरण के मानदंडों में ढील दी है।

उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लक्ष्य से नागरिकों की सुविधा के लिए अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने हेतु मानदण्डों में छूट दी है। जिन कॉलोनियों तक पहुंचने वाली सड़क 6 मीटर या इससे अधिक तथा आंतरिक सड़कें 3 मीटर या इससे अधिक चौड़ी हैं, अब उन्हें नियमित किया गया है।

इन कॉलोनियों के नियमित होने से निवासियों को बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अनधिकृत कॉलोनियां पालिका क्षेत्र से बाहर भी बन गई थी। इनमें रहने वाले लोग वर्षों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। हमने उनकी पीड़ा को समझा है और पहली बार पालिका क्षेत्रों से बाहर की कॉलोनियों को भी नियमित करने का काम किया है।

उन्होंने बताया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति ने नगरपालिका क्षेत्र से बाहर बसी हुई कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं व नागरिक सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर विचार-विमर्श किया और कुछ सिफारिशें की। इनके आधार पर सरकार ने कम से कम 2 एकड़ क्षेत्र में बसी अलग-थलग कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया। हालांकि, यह नियम उस कॉलोनी पर लागू नहीं होगा, जो किसी अन्य अधिकृत, लाइसेंसशुदा अथवा नियमित कॉलोनी के समीप है और उसके लिए रास्ता उसी कॉलोनी के अंदर से जाता है।

कॉलोनी के नियमितीकरण के लिए संबंधित जिले के सदस्य सचिव (संयोजक) डीटीपी को देना होगा आवेदन

मुख्यमंत्री ने कहा कि पालिका क्षेत्र से बाहर की कॉलोनी को नियमित करवाने के लिए संबंधित पक्ष को संबंधित जिले के सदस्य सचिव (संयोजक) डी.टी.पी. के पास आवेदन जमा करवाना होगा, जो इन आवेदनों को डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रूटनी कमेटी को भेजेगा। उन्होंने कहा कि पहले से विकसित कॉलोनियों में पंजीकृत नागरिक कल्याण समिति नहीं होंगी, समिति बनाकर उसे पंजीकृत करवाने में भी काफी समय लगता है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि पंजीकृत नागरिक कल्याण समिति या डेवलपर या कॉलोनी के कम से कम 5 निवासियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। इनके बाद प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सोसायटी को पंजीकृत करवाया जा सकता है।

'ए' और 'बी' श्रेणी की कॉलोनियों में पहुंच सड़क कम से कम 6 मीटर चौड़ी व आंतरिक सड़कों की कम से कम चौड़ाई 3 मीटर होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सड़क की चौड़ाई और वाणिज्यिक क्षेत्र मानदंडों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'ए' और 'बी' श्रेणी की कॉलोनियों में पहुंचने के लिए कम से कम 6 मीटर चौड़ा मार्ग होना चाहिए। आंतरिक सड़कों की कम से कम चौड़ाई 3 मीटर होनी चाहिए। इसके अलावा, श्रेणी 'सी' और 'डी' में आने वाली कॉलोनियों के लिए, किसी भी चौड़ाई के मुख्य रास्ते वाले आवेदनों पर विचार करने का प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा कि इन आवासीय कालोनियों में वाणिज्यिक क्षेत्र 4 प्रतिशत से अधिक हो सकता है। जिन आवासीय कॉलोनियों में कमर्शियल क्षेत्र पहले ही 4 प्रतिशत से अधिक विकसित है या कमर्शियल गतिविधियों के लिए आवंटित अथवा पंजीकृत है, उन कॉलोनियों को भी अतिरिक्त शुल्क के साथ नियमित किया जाएगा। लेकिन इसमें मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल और बैंक्वेट हॉल आदि शामिल नहीं होंगे।

इसके अलावा, पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ने वाली आवासीय कॉलोनियों को नियमित करने के लिए जो विकास शुल्क किये गए हैं, वे अविकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 8 प्रतिशत तथा विकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत देय होगा।

पालिका क्षेत्र में विकास शुल्क सभी तरह के क्षेत्र पर 5 प्रतिशत होगा।

मनोहर लाल ने कहा कि वाणिज्यिक क्षेत्र 4 प्रतिशत होगा और इस सीमा से अधिक वाणिज्यिक क्षेत्र पर विकास शुल्क का तीन गुणा देय होगा। कलेक्टर रेट विकास प्लान के रिहायशी जोन में पड़ने वाली कृषि भूमि पर लागू कलेक्टर रेट की दरों के बराबर होगा। पालिका क्षेत्र में विकास शुल्क सभी तरह के क्षेत्र पर 5 प्रतिशत होगा। उन्होंने कहा कि हम नागरिकों पर एक बार में ही विकास शुल्क का भार नहीं डालना चाहते। इसलिए विकास शुल्क की अदायगी को भवन नक्शों, बिक्री अथवा खरीद की स्वीकृति आदि से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि पालिका क्षेत्र से बाहर के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अंतिम प्राधिकारी डीएलएससी के अध्यक्ष को बनाया गया है। पालिका क्षेत्र में ये शक्तियां डिविजनल कमिश्नर के पास होंगी। हमने ऐसी कॉलोनियों में सेल डीड पर पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए 1 जुलाई, 2022 से पहले जिन्होंने बिक्री के लिए सेल डीड या एग्रीमेंट टू सेल पंजीकृत करवा रखे थे, उन्हें बेचा हुआ माना जाएगा।

500 वर्ग मीटर तक के पार्क, खुले स्थान और सामुदायिक हॉल का किया गया प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली कॉलोनियों में रहने के लिए बेहतर वातावरण बनाने हेतु 500 वर्गमीटर तक के पार्क, खुली जगहों और सामुदायिक भवन के प्रावधान किए जाएंगे। इसके लिए उन कॉलोनियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनमें डेवलपर के स्वामित्व वाला क्षेत्र बेचा नहीं गया है।

इसके अलावा, इन कॉलोनियों में अग्निशमन मानदंडों में ढील देने की जरूरत है, जिनके लिए डेवेलपर/आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे और अग्निशमन विभाग से लिखित में परामर्श किया जाएगा। इस बारे संबंधित डेवेलपर/आर.डब्ल्यू.ए. संबंधित उपायुक्त और जिला नगर योजनाकार को सूचित करेंगे।

इन आवासीय कॉलोनियों में पहले से बने सभी मकानों की वर्तमान स्थिति बरकरार रखी जाएगी।

मनोहर लाल ने कहा कि इन आवासीय कॉलोनियों में पहले से बने हुए सभी मकानों की वर्तमान स्थिति बनी रहेगी। नीतिगत निर्देशों की अधिसूचना से पहले विभाग द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण भी करवाया गया था, इसलिए ऐसे निर्देशों के तहत कवर की गई कॉलोनियों में भूखंडों पर निर्माण किए जाने की संभावना है। अतः आवेदन जमा करने की समय सीमा को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

लेम्बोर्गिनी की पहली ईवी कॉन्सेप्ट आधिकारिक तौर पर हुई पेश, नाम है लैंजाडोर

लेम्बोर्गिनी ने 2023 मोंटेरे कार वीक में आधिकारिक तौर पर Lanzador (लैंजाडोर) कॉन्सेप्ट को पेश किया है। यह ब्रांड का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन है और चौथी सीरीज का प्रॉडक्शन लेम्बोर्गिनी होगा। वाहन निर्माता ने 2021 में डीकार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में अपनी रणनीति और अपने रोडमैप का एलान किया था। लैंजाडोर कॉन्सेप्ट से पहले, ब्रांड ने Revuelto (रेवुएल्टो) का प्रदर्शन किया था जो आइकॉनिक एवेंटाडोर का रिप्लेसमेंट है और V12 प्लग-इन हाइब्रिड के साथ आता है। लैंजाडोर उस सीरीज मॉडल के बारे में जानकारी देता है जिसे 2028 में बनाया जाएगा।

लेम्बोर्गिनी का कहना है कि उन्हें एक हाई परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने में 2 साल लग गए जो ब्रांड के दिल और आत्मा के लिए सच है। ऑल-इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट एक ग्रैंड टूरर है जिसमें 2+2 बैठने की व्यवस्था है। यह पहली बार नहीं है कि निर्माता चार दरवाजों वाला वाहन बना रहा है। अतीत में, उन्होंने Estoque (एस्टोक) कॉन्सेप्ट शोकेस किया था जो चार दरवाजों वाली बॉडी स्टाइल के साथ आया था।

लैंजाडोर में प्रत्येक एक्सल पर एक हाई-पावर इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका मतलब है कि इसमें परमानेंट ऑल-व्हील ड्राइव होगा। इसमें रियर एक्सल पर ई-टॉर्क वेक्टरिंग की सुविधा होगी। लेम्बोर्गिनी का कहना है कि अधिकतम पावर उत्पादन एक मेगावाट से ज्यादा होगा जो लगभग 1,340 बीएचपी है। निर्माता के अनुसार, लैंजाडोर ₹नई पीढ़ी की हाई-परफॉर्मेंस बैटरी से चलेगी, जो लंबी दूरी भी सुनिश्चित करती है।₹ लैंजाडोर Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), लेम्बोर्गिनी डिनमिका वेइकोलो इंटीग्रेटा (एलडीवीआई) के साथ आएगा जो एक ड्राइविंग डायनेमिक्स कंट्रोल सिस्टम है। ऐसे कई सेंसर और एक्चुएटर होंगे जिन्हें सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाएगा जो सटीक ड्राइविंग व्यवहार सुनिश्चित करता है। इसमें एक्टिव एयरोडायनैमिक्स भी होगा। ये न सिर्फ कॉर्नरिंग क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन में ड्राइविंग रेंज को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। एयरोडायनामिक्स में

Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA), एयरोडिनेमिका लेम्बोर्गिनी एटिवा (एएलए) सिस्टम भी शामिल है जो Huracán Performante (हुराकैन परफॉर्मेंट) और Aventador SVJ (एवेंटाडोर एसवीजे) जैसी कारों में इस्तेमाल की जाने वाली एक मशहूर टेक्नोलॉजी है।

लेम्बोर्गिनी टिकाऊ सामग्री का इस्तेमाल करेगी। इसमें सस्टेनेबल रंगा हुआ चमड़ा, 100 प्रतिशत मेरिनो ऊन, रीजेनरेटेड कार्बन, रीसाइकिल की गई प्लास्टिक से बनी सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के लिए 3डी प्रिंटेड प्रोसेस होगी।

2025 तक लॉन्च होगी रेनॉ क्विड ईवी, 10 लाख से कम हो सकती है कीमत

भारत में क्विड इलेक्ट्रिक को लॉन्च करने वाली है। उम्मीद है कि इसे 2025 तक लॉन्च किया जाएगा और यह उन्नत क्विड आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। मौजूदा क्विड के कंपेरिज़न में इसमें बदलाव किए जाएंगे। भारत में क्विड इलेक्ट्रिक को लॉन्च करने वाली है। उम्मीद है कि इसे 2025 तक लॉन्च किया जाएगा और यह उन्नत क्विड आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। मौजूदा क्विड के कंपेरिज़न में इसमें बदलाव किए जाएंगे। क्विड ईवी वर्तमान में चीन और यूरोप में डेसिया और डोंगफेंग जैसे विभिन्न नेमप्लेट के तहत बेची जाती है। लॉन्च होने पर ये गाड़ी टाटा टियागो, सिट्रोएन ईसी3 और एमजी की कॉम्पैक्ट ईवी, कॉमेट को टक्कर देगी।

अगले 3 सालों में ईवी सेगमेंट 25% सेल को बढ़ाना है मर्सिडीज़-बेंज़ का लक्ष्य

भारत में बढ़ रही ईवी मार्केट में मर्सिडीज-बेंज को काफी उम्मीद है। निर्माता को उम्मीद है कि अगले तीन वर्षों में उसका ईवी पोर्टफोलियो बढ़कर उसकी सेल कुल का 25% होगा। मर्सिडीज-बेंज ने बीते दिनों जीएलसी को लॉन्च किया था।

भारत में बढ़ रही ईवी मार्केट में मर्सिडीज-बेंज को काफी उम्मीद है। निर्माता को उम्मीद है कि अगले तीन वर्षों में उसका ईवी पोर्टफोलियो बढ़कर उसकी सेल कुल का 25% होगा। मर्सिडीज-बेंज ने बीते दिनों जीएलसी को लॉन्च किया था। कंपनी के M.D और CEO संतोष अय्यर ने कहा कि ऑटोमेकर भारत में आने वाले 12 से 18 महीनों में तीन से चार ईवी लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ संतोष अय्यर ने खुलासा किया कि ऑटोमेकर अगले 12 से 18 महीनों में भारत में तीन से चार नए ईवी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अय्यर ने कहा कि जैसे-जैसे नए ईवी पेश किए जाते हैं, भारतीय उपभोक्ताओं के बीच इसे तेजी से अपनाया जाना चाहिए, जिससे धीरे-धीरे बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा, ₹अगले तीन वर्षों के भीतर, हमारा अनुमान है कि भारत में हमारी बिक्री का 25 प्रतिशत हिस्सा ईवी का होगा।₹ अय्यर ने इस बात पर जोर दिया कि कई मर्सिडीज-बेंज कार मालिकों के पास पहले से ही अपने घरों या कार्यस्थलों पर चार्जिंग बुनियादी ढांचे हैं, जो संभावित रूप से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर बहुत अधिक भरोसा किए बिना इलेक्ट्रिक वाहनों में संक्रमण को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। उन्होंने कुछ राज्यों द्वारा ईवी पर रोड टैक्स से छूट प्रदान करने की क्षमता के बारे में आशावाद व्यक्त किया।

विनिर्माण क्षमता के बारे में, अय्यर ने उल्लेख किया कि कंपनी का संयंत्र, जो पुणे में 100 एकड़ से अधिक में फैला है, सालाना 20,000 इकाइयों तक उत्पादन करने की क्षमता रखता है, एक क्षमता जिसे संभावित रूप से 40,000 तक बढ़ाया जा सकता है। प्लांट में चल रहा निवेश लगभग 2,700 करोड़ है, जीएलसी मॉडल लॉन्च के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ का निवेश किया गया है। 20,000 से 40,000 कारों तक उत्पादन क्षमता का विस्तार चरणों में होने की उम्मीद है, शुरुआती 20,000 कारों को जल्द ही हासिल किया जाएगा, इसके बाद अगले दो से तीन वर्षों में और प्रगति होगी।

दिल्ली-शिमला हाईवे पर दिसंबर से दौड़ेंगे ईवी, ट्रायल रन शुरू

नेशनल हाईवे फार इलेक्ट्रिक व्हीकल (एनएचईवी) द्वारा दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर शिमला तक के लगभग 360 किलोमीटर के मार्ग पर ट्रायल रन शुरू किया गया है। इस ट्रायल रन के दौरान बुनियादी ढांचे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभाव ट्रैफिक पर प्रभाव चार्जिंग स्टेशनों की दक्षता चार्जिंग के दौरान लगने वाला समय पर्यावरण सुधार जैसे कारकों का अध्ययन किया जाएगा।

सोनीपत। दिल्ली और हरियाणा के लोग अब अपनी इलेक्ट्रिक कार से हिमाचल पहुंच सकेंगे। नेशनल हाईवे फार इलेक्ट्रिक व्हीकल (एनएचईवी) द्वारा दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर शिमला तक के लगभग 360 किलोमीटर के मार्ग पर ट्रायल रन शुरू किया गया है।

तीन महीने तक चलने वाले इस ट्रायल रन के दौरान बुनियादी ढांचे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभाव, ट्रैफिक पर प्रभाव, चार्जिंग स्टेशनों की दक्षता, चार्जिंग के दौरान लगने वाला समय, पर्यावरण सुधार जैसे कारकों का अध्ययन किया जाएगा। अगले तीन साल में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

इससे न केवल ईवी-फ्रेंडली हाईवे नेटवर्क स्थापित होगा, बल्कि प्रदूषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। इस ट्रायल रन का पहला स्टापेज सोनीपत होगा। फिलहाल यहां एनएच-44 (दिल्ली-सोनीपत-पानीपत-अंबाला) पर गुरुग्राम की तर्ज पर 100 चार्जिंग प्वाइंट की क्षमता का प्रोटोटाइप वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। शुरुआत में ही इसे सोलर एनर्जी आधारित बनाया जाएगा ताकि दिन के समय वाहन चार्जिंग की लागत कम आए।

360 किलोमीटर के मार्ग पर ई-वाहनों के लिए सुविधाएं देने को ट्रायल रन शुरू

अगले तीन साल में हर 20 किमी पर होंगे चार्जिंग स्टेशन, सौर उर्जा पर रहेगा जोर

70,341 इलेक्ट्रिक वाहन हैं हरियाणा में

5,000 से ज्यादा ईवी हैं सोनीपत जिले में

2.35 लाख ईवी रजिस्टर्ड दिल्ली में

ट्रायल में इनका अध्ययन होगा

ब्रेक डाउन होने पर 30 मिनट में सहायता पहुंचना

चोरी रोकने के लिए एंटी थेफ्ट सिस्टम यानि एटीएस स्थापित करना

प्रति किमी ईवी चलाने का खर्च कितना हो रहा है

बस में प्रति सवारी कितना खर्च आएगा

वर्षा के दौरान ईवी संचालन की दिक्कत

वाहन चार्जिंग में लगने वाले समय के सदुपयोग के लिए चार्जिंग स्टेशन पर शापिंग सेंटर, फूड कोर्ट, एटीएम, बैंक, टायलेट्स, रेस्ट रूम, बच्चों के खेलने की व्यवस्था की जाएगी। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में बड़ी संख्या में लोग अब ईवी खरीद रहे हैं। प्रदेश सरकार सब्सिडी भी दे रही है। ट्रायल रन के दौरान दिल्ली से शिमला के बीच दो बस और 20 कारें चलाई जाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक ट्रायन रन के बाद दिसंबर के अंत तक लोग अपने ईवी से दिल्ली से शिमला का सफर तय कर सकते हैं।

दो साल पहले एनएच-44 ई-हाईवे घोषित हुआ था

वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने एनएच-44 को ई-हाईवे घोषित किया था। सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिल्स लिमिटेड यानी भेल को यहां ईवी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम सौंपा था। भेल ने सोनीपत में एथनिक इंडिया, समालखा, घरौंडा, करनाल में कर्ण लेक और अंबाला में चार्जिंग प्वाइंट लगाए थे। लेकिन न तो ट्रायल रन किया गया और न ही बड़े चार्जिंग स्टेशन बनाए गए।

इसके चलते यह हाईवे ईवी फ्रेंडली नहीं बन सका। ऐसे में भारत सरकार के ईज आफ डूइंग बिजनेस प्रोग्राम के तहत नेशनल हाईवे फार ईवी द्वारा यहां स्टेक होल्डर्स के साथ संयुक्त रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम शुरू किया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए एनएचईवी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अभिजीत सिन्हा ने कहा- दिल्ली-आगरा और दिल्ली-जयपुर ई हाईवे पर टेक-ट्रायल रन सफल रहा था। अब दिल्ली-शिमला मार्ग पर ट्रायल रन शुरू किया गया है। इस मार्ग पर नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे ईवी संचालकों को कोई दिक्कत नहीं आएगी।

विदेश में मंदिरों पर हमले, राष्ट्रवादी चुप क्यों

योगेंद्र योगी

विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे तत्व देश की संप्रभुता और सुरक्षा में बाधा डालेंगे तो भारत कड़ी प्रतिक्रिया देने में संकोच नहीं करेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि कनाडा के राजनेता आंखें मूंदकर बैठे हुए हैं।

देशभक्ति और हिन्दुत्व का दंभ भरने वाले संगठन कनाडा, ब्रिटेन और अमरीका में खालिस्तान समर्थकों द्वारा मंदिरों और अन्य भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमले पर आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी साधे हुए हैं। देश के विभाजन के विदेशी प्रयासों पर इन संगठनों की यह चुप्पी समझ से परे है। नूंह में धार्मिक रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर आक्रामक रुख अपनाने वाले संगठनों ने विदेशों में सरेआम भारत और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान पर किसी तरह का धरना-प्रदर्शन तो दूर, बल्कि सख्त प्रतिक्रिया तक देना जरूरी नहीं समझा। ऐसे मामलों में विदेशी सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विदेशों में हमले की नई कड़ी में खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में एक बार फिर मंदिर पर हमला करके देश को चुनौती दी है। खासतौर पर कनाडा में भारत विरोधी ताकतों की हरकतें बेलगाम होती जा रही हैं। खालिस्तान समर्थकों के मंदिर पर लगातार हो रहे हमले के बजाय यही हमले यदि किसी मुस्लिम संगठन द्वारा किए गए होते तो कथित देशभक्त संगठन अब तक आसमान सिर पर उठा लेते। इसके विपरीत खालिस्तान समर्थकों के हमलों के लेकर मौन धारण किए हुए हैं।

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक बार फिर से खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर में तोडफोड़ की। खालिस्तानियों ने मंदिर में तोडफोड़ की और इसे नुकसान पहुंचाया। इसके बाद जाते वक्त मंदिर के मुख्य दरवाजे पर खालिस्तान जनमत संग्रह के पोस्टर चिपका दिए। खालिस्तानियों की ये पूरी करतूत पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वर्ष 2023 की शुरुआत से तो पूरे कनाडा में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने की श्रृंखला शुरू हो गई है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से लेकर आपत्तिजनक भित्तिचित्र, सेंधमारी और बर्बरता की करीब आधा दर्जन घटनाएं हुई हैं। मौजूदा घटना कनाडा में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की इस साल में तीसरी है। 31 जनवरी को ही कनाडा के ब्रैम्पटन में एक प्रमुख हिंदू मंदिर में तोडफ़ोड़ की गई थी। इसके ऊपर भारत विरोधी बातें भी लिखी गईं।

खालिस्तानियों की इस हरकत से वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच खासा नाराजगी थी। इस साल अप्रैल में ही कनाडा के ओंटारियो में भी एक हिंदू मंदिर खालिस्तानियों के निशाने पर आया था। इस पर भी भारत विरोधी नारों को लिखा गया। कनाडा के ओंटारियो में ही एक गांधी प्रतिमा को तोड़ दिया था। मार्च के आखिरी हफ्ते में कनाडा के बर्नबाई में एक यूनिवर्सिटी के

अंदर स्थित गांधीजी की प्रतिमा को भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद भारत की ओर से सख्त एतराज जताया गया। कुछ दिनों पहले खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाते हुए वाणिज्य दूतावास को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पिछले साल जुलाई में, ग्रेटर टोरंटो एरिया में रिचमंड हिल में विष्णु मंदिर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को भद्दे शब्दों से पोत दिया गया था, जिसके बाद भारतीय समुदाय ने प्रदर्शन किया था। बीते दिनों भारतीय समुदाय के लोगों ने भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों के उत्पात के विरोध में प्रदर्शन किया जिसके बाद कनाडा की सरकार ने कहा कि वे भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाएंगे। कनाडा में खालिस्तानियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं वर्षगांठ पर ब्रैम्पटन में एक परेड का आयोजन किया गया था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाती एक झांकी निकाली गई। फिर बीते दिनों भारतीय दूतावास के बाहर कुछ पोस्टर लगे नजर आए जिन पर भारतीय राजनयिकों की फोटो थी और इसके जरिए उन्हें निशाना बनाने की बात कही गई थी। इन घटनाओं को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कनाडा की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए क्योंकि ट्रूडो सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है।

विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे तत्व देश की संप्रभुता और सुरक्षा में बाधा डालेंगे तो भारत कड़ी प्रतिक्रिया देने में संकोच नहीं करेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि कनाडा के राजनेता आंखें मूंदकर बैठे हुए हैं। कनाडा खालिस्तान के आतंकियों का बचाव करने की कोशिश किस तरह से कर रहा है, प्रधानमंत्री के बयानों से यह साफ झलकता है कि आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से हिचकिचा रहा है। कनाडा के भारत मूल के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान के बढ़ते प्रभाव को पूरी तरह से नकार दिया था और उल्टा इस मामले में भारत को ही घेर लिया। पीएम ट्रूडो ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'वो (भारत सरकार) गलत हैं। हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की है।' खालिस्तान समर्थकों के मामले में कनाडा की तरह ब्रिटेन और अमरीका का रवैया भी लिजलिजा है। खालिस्तान समर्थक तत्वों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लंदन में भारतीय उच्चायोग ने भारतीय ध्वज को नीचे खींच लिया। तिरंगे को प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने अलगाववादी खालिस्तानी झंडे लहराते हुए और खालिस्तान समर्थक नारे लगाए। इस वीडियो के सामने आने के बाद भारत ने इस मामले में पूरी तरह से सुरक्षा की अनुपस्थिति पर ब्रिटिश उप उच्चायुक्त को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा था। उन्हें वियना कन्वेंशन के तहत यूके सरकार के बुनियादी दायित्वों के संबंध में याद दिलाया गया। भारतीय दूतावास पर किए गए हमले का मुद्दा ब्रिटेन की संसद में भी गूंजा। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि हम अभी भी इस देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हम उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को लेकर क्या फैसला ले सकते हैं। बॉब ब्लैकमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता पेनी मोर्डंट को संबोधित करते हुए कहा कि खालिस्तानी गुंडों की भारतीय उच्चायोग के बाहर जो गुंडागर्दी हुई, वह इस देश के लिए पूरी तरह से अपमानजनक है। इतने सालों में यह 6वीं बार है जब उच्चायोग पर इसी तरह से हमला किया गया है। इसके जवाब में सदन के नेता पेनी मोर्डंट ने कहा कि हम लंदन स्थित भारतीय दूतावास की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि यह तय करना पुलिस और क्राउन प्रॉसीक्यूशन का काम होगा कि वारंट और आपराधिक कार्यवाही से जुड़ी कार्रवाई की जरूरत है या नहीं। बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि इसी तरह के हमले कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी किए गए। हम अभी इस देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। क्या हम सरकार के समय में इस बात पर बहस कर सकते हैं कि इन आतंकवादियों को इस देश में प्रतिबंधित करने के लिए हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। पेनी मोर्डंट ने अपनी प्रतिक्रिया में बॉब ब्लैकमैन को हमले की निंदा करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स को आश्वासन दिया कि यूके सरकार भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को गंभीरता से लेती है। अमरीका बेशक भारत से दोस्ती और बेहतर रिश्ते बनाने का कितना ही दंभ भरे, किन्तु अमरीकी जमीन पर भारत विरोधी ताकतों की सक्रियता के मामले में राष्ट्रपति बाइडन प्रशासन ने भी कभी सख्ती नहीं दिखाई। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में खालिस्तान समर्थकों की तरफ से आगजनी की कोशिश की गई। खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास में आग लगा दी, लेकिन सैन फ्रांसिस्को अग्निशमन विभाग ने इसे तुरंत बुझा दिया। आग की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। खालिस्तान समर्थकों ने घटना के संबंध में एक वीडियो भी जारी किया। अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्वीट पर भारतीय वाणिज्य दूतावास के खिलाफ कथित बर्बरता और आगजनी के प्रयास की कड़ी निंदा कर अपने दायित्वों की इतिश्री कर ली। इससे पहले अमेरिका में मार्च के महीने में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थकों ने नारेबाजी की थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से लगाए गए अस्थायी सुरक्षा घेरे को भी तोड़ दिया था। इसके अलावा वाणिज्य दूतावास परिसर के अंदर दो खालिस्तानी झंडे लगा दिए थे।

संपादक की कलम से

अदालत की नई शब्दावली

सर्वोच्च अदालत ने नई शब्दावली जारी की है। यह प्रयास खासकर महिलाओं के सम्मान, उनकी गरिमा और समता के मद्देनजर किया गया है। इस लैंगिक और बेहतर पहल के लिए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। हमारी अदालतों की भाषा वाकई कबीलाई और मध्यकालीन संस्कारों और सोच से प्रभावित है। अदालतों में भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, क्योंकि अधिकांश न्यायाधीश, वकील और कर्मचारी पुरुष हैं। महिलाओं की उपस्थिति न्यूनतम है, लेकिन भाषा के स्तर पर वही पुराना लैंगिक वर्चस्व का भाव है। बेशक याचिका हो या पुलिस, जांच एजेंसी का आरोप-पत्र अथवा वकीलों की बहस और न्यायाधीशों के फैसले हों, भाषाई स्तर बेहद आपत्तिजनक और तिरस्कारवादी रहा है। मसलन-वेश्या, बिन ब्याही मां, बदचलन, छोड़ी हुई औरत, रखैल आदि शब्द कमोबेश 21वीं सदी की भाषा के नहीं हो सकते। दरअसल भाषा हमारी चेतना को अभिव्यक्त करती है, लिहाजा मानसिक सोच को भी स्पष्ट करती है।

कानून भाषा के जरिए ही जिंदा है। अदालतों में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, उनका हमारी जिंदगी पर बहुत प्रभाव होता है। कटघरे और अदालत में मौजूद महिला किसी की बेटी, बहन, बहू और पत्नी ही है, लिहाजा अपराध के बिना उसे लांछित क्यों किया जाए? प्रधान न्यायाधीश ने यह सामाजिक, भाषायी बीड़ा उठाया है, यकीनन इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 43 शब्दों को फिलहाल रेखांकित करते हुए एक पुस्तिका जारी कराई है। उसकी शब्दावली में मां, यौनकर्मी, गृहिणी, अविवाहित महिला, होममेकर, फूहड़ या पवित्र महिला के स्थान पर सिर्फ 'महिला', कीप-रखैल-मिस्ट्रेस के लिए 'गैर मर्द से संबंध' आदि शब्दों के प्रयोग के संशोधन किए गए हैं।

फिलहाल यह बेहद सीमित पहल है। महिलाओं के अलावा भी कुछ और शब्द जोड़े गए हैं, लेकिन अभी यह अनुसंधान जारी रखना चाहिए कि किन और शब्दों को बेहतर और सभ्य बनाया जा सकता है। पहली चुनौती यह है कि क्या अदालतों में इन बेहतर शब्दों का चलन तुरंत प्रभावी हो जाएगा? जो नए शब्दों के स्थान पर पुराने शब्दों को ही दोहराते रहेंगे, उनके लिए अदालत के निर्देश क्या होंगे? अथवा उन्हें दंडित भी किया जा सकेगा? न्यायपालिका में करोड़ों मामले लंबित या विचाराधीन हैं। उनकी भाषा बदलने के आधार और नियम क्या होंगे? अब नई विश्व-व्यवस्था और नए भारत में परिवार का 'कमाऊ' और 'रोटी-प्रदाता' सदस्य पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी हैं। अलबत्ता वे यौन और घरेलू सेवाएं भी प्रदान करती हैं। प्रकृति ने उन्हें ही 'मातृत्व' का वरदान दिया है, लिहाजा शब्दों और सोच का इस्तेमाल भी सभ्य और समता के स्तर पर किया जाना चाहिए। चूंकि अदालत से सीधा संबंध पुलिस, जांच एजेंसियों का है, लिहाजा प्रधान न्यायाधीश नई शब्दावली के लिए पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय और अन्य संबद्ध विभाग से भी आग्रह कर सकते हैं। हमारा मानना है कि देश की समूची व्यवस्था में कमोबेश 'भाषायी परिवर्तन' को जरूर लागू किया जाना चाहिए। तभी हम व्यावहारिक और आदर्श, सामाजिक तौर पर 'लैंगिक समानता' और 'लैंगिक गरिमा' की बात कर सकते हैं। बहरहाल नई शब्दावली का प्रयोग भी इसी संदर्भ में किया गया है कि भरी अदालत में औरत को कलंकित या लांछित न किया जाए। जो पुस्तिका जारी की गई है, उसे प्रवचन के बजाय व्यवहार में लिया जाना चाहिए।

चर्चा

बेघर शहरी विकास

प्राकृतिक आपदा में लावारिस हुआ अपना घर भी, पूरे मोहल्ले ने रेंगना शुरू कर दिया था। हिमाचल में प्रकृति के सबसे बड़े प्रकोप ने हमारी करतूतों को कोसा है, अतीत के विश्राम को रोका है। सरपट दौड़ती-भागती जिंदगी को विराम की सरहद बताई है, तो कई सवाल सरकारी कामकाज के ढर्रे, सिफारिशों-फरमाइशों और सियासी फेहरिस्त की आजमाइशों से भी हैं। आश्चर्य होता है कि जिस शहरी विकास विभाग के दायित्व, प्राथमिकता और जवाबदेही से हम हिमाचली शहरों में सुकून से भविष्य देखना चाहते हैं, वही बेघर हो गया। शहरी विकास के मुख्यालय का भवन खाली करवाना पड़ गया। जाहिर है यह इमारत वहीं थी, बल्कि इसके भीतर प्रदेश की बुलंदी, शहरीकरण के आश्वासन और भविष्य को रेखांकित करती परिकल्पना भी थी, जो अपने ही कारणों से विस्थापित हो गया। इतना ही नहीं हाउसिंग बोर्ड की जाखू स्थित कालोनी को बचने के लिए शरण की जरूरत आ पड़ी है, तो कांगड़ा में भी कालोनी के छह घर टूट फूट की जद में आ गए हैं। यानी हम ऐसा भविष्य दिखा या खोज रहे हैं, जिसका कोई वारिस नहीं। यह इसलिए कि कमोबेश हर सरकार ने तमगे ढूंढे और इन्हीं बुर्जियों पर विकास अंधा हो गया। हम शाम होने पर चौंकते हैं कि अंधेरे मिटाने के लिए अब कोई दीपक चाहिए, वरना सो जाने के लिए तो यही पहर काफी है। हम तहें जमा कर केवल सत्ता के लाभ देख रहे हैं।

न कोई अनुसंधान, न कोई संकल्प और न ही कोई आर एंड डी। हमारे माथे पे घास उगी है, इस कद्र कि दिमाग तक रेंग कर भी नहीं जा सकते। हमने राजनीतिक घासतंत्र विकसित कर लिया है। आप विधानसभा की बहस देख लीजिए और पूछ लीजिए कि हर पक्ष ने किस खुराफात के लिए सदन से बहिर्गमन किए। क्या आज तक के हिमाचली इतिहास में विधानसभा की बहस ने आम आदमी और प्रदेश के अस्तित्व के प्रश्नों का सही सही हल ढूंढा। बताइए नदियों, नालों, खड्डों, कूहलों का बावडियों के अस्तित्व पर कितनी चिंता हुई। हमने एचआरटीसी पर चर्चा यह की कि नए रूट बढ़ा दिए जाएं या बस डिपो की संख्या में इजाफा कर दिया जाए। क्या हमने ऐसे रास्ते या रूट खोजे जहां मौसम की बेरुखी पर भी परिवहन चलता। परिवहन के विकल्प होते, तो सेब इस वक्त पेटियों में नहीं सड़ता। कोई एक रज्जु मार्ग बता दें, जो इस समय शिमला व कुल्लू के सेब को मंडी तक ले आता। हमने देखे कई नेता हरी झंडियों की पोशाक में, लेकिन ये उद्घाटन लतीफा बन गए। शिमला में जमींदोज भवन, गिरते पेड़ और चकमा देते पहाड़ों की फितरत में समाया रोष आखिर किसके वर्चस्व की निशानी है। अगर शहरी विकास की वकअत होती, तो अपनी इमारत को ही थाम लेता, लेकिन राजधानी मर रही है और इसकी इत्तिला तक यह विभाग नहीं दे पाया। आखिर प्रदेश की राजधानी की परिकल्पना में हमने किया ही क्या। कभी पेयजल के नाम पर पीलिया और कभी परिवहन के नाम पर ट्रैफिक जाम में फंसे शहर की आबरू इतनी कमजोर क्यों हो गई। जरा पूछें आज तक के तमाम शहरी विकास मंत्रियों से और खास तौर पर पिछली सरकार के तत्कालीन दो मंत्रियों से कि उनके लिए शिमला स्मार्टसिटी परियोजना सिर्फ कंक्रीट की ठेकेदारी क्यों बन गई। पत्थरों के डंगों को हटाकर कंक्रीट का लेबल चढ़ा कर या सारे शहर में लोहे का परचम फैला कर उन्होंने देखा क्या। विडंबना यह भी है कि सरकारी महकमों में 'राजनीतिक औलाद' काम कर रही है और नेतृत्व के लिए ऐसे मंत्री पुरस्कृत हैं जिन्हें सिर्फ अगले चुनाव के लिए केवल अपनी विधानसभा क्षेत्र की परिक्रमा करनी है।

प्रो. सुरेश शर्मा

राष्ट्रीय आपदा घोषित हो यह महाप्रलय

इस समय केन्द्र सरकार, विपक्षी दलों तथा सभी लोगों को इस विनाशलीला को समाप्त करने के लिए सहयोग देकर हाथ बढ़ाना चाहिए'

मात्र चौबीस घण्टे में हिमाचल जैसे छोटे राज्य में पचपन लोगों का अकारण और असमय मौत का शिकार हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। तेरह और चौदह अगस्त 2023 का दिन भयंकर वर्षा, जलप्रपात तथा भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश के लोगों को कभी न भूलने वाला दर्द दे गया। प्रदेश का जनमानस डर के साये में जीवन यापन कर रहा है। सडक़ें, इमारतें, गाडियां, बिजली तथा पानी की योजनाएं, पर्यटक स्थल, भौतिक संसाधन, सभी विनाशलीला का शिकार हो रहे हैं। चारों ओर भयंकर तबाही का आलम है। हमेशा से मनुष्य द्वारा प्रकृति पर बार-बार उत्पात करने तथा सजा भुगतने का यह क्रम अनवरत रूप से चल रहा है। यह तो निश्चित है कि हर वर्ष सर्दी, गर्मी तथा बरसात होगी तथा यह भी सर्वविदित है कि जहां मानवीय जीवन होगा वहां पर आग, बाढ़, तूफान, सूखा, अकाल, भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकम्प, सुनामी, समुद्री तूफान, बिजली गिरने, बादल फटने तथा महामारी की संभावना भी होगी। मौसम विभाग के रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट तथा चेतावनियां भी अब आम बात हो गई है। यह भी सत्य है कि हम आपदाओं को समाप्त तो नहीं कर सकते बल्कि उनको कम करने के लिए प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए हर पल तत्पर एवं सचेत रहना हमारी आवश्यकता तथा प्राथमिकता है। यह सरकार, प्रशासन, व्यवस्था तथा समाज का सामूहिक कार्य है। यह भी स्वीकार करना होगा कि हम समय रहते आपदाओं की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयारी नहीं करते। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है तथा प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। पहाड़ी राज्यों की मुश्किलें एवं परेशानियां मैदानी राज्यों की अपेक्षा अधिक एवं अलग होती हैं।

इस संदर्भ में अंधाधुंध विकास, भवन निर्माण, औद्योगिकीकरण, जंगलों का कटान, सडक़ों का निर्माण, बिजली परियोजनाओं के लिए बांध का निर्माण, बारूद से पहाड़ों का सीना छलनी होना तथा विद्युत उत्पादन के साथ योजनाओं की समीक्षा एवं विश्लेषण होना भी आवश्यक है। यह ठीक है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, सडक़ों, पुलों, विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, बड़ी-बड़ी इमारतों तथा कारखानों का निर्माण भी लोगों व प्रदेश की आवश्यकता है, लेकिन भौतिक विकास मानवीय जीवन तथा प्रकृति के विनाश की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आपदाओं की तीव्रता तथा इनकी आवृत्ति में कमी का प्रयास किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वीकार किया कि मात्र दो दिनों में 55 लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने माना कि विगत पचास वर्षों में इतनी भारी वर्षा नहीं हुई। प्रदेश में इस मॉनसून में अभी तक लगभग 150 लोग मारे जा चुके हैं। लगभग 1200 सडक़ें भूस्खलन के कारण बन्द हो चुकी हैं। एचआरटीसी के लगभग 3700 रूट बन्द हो चुके हैं। बिजली के 4500 ट्रांसफार्मर तथा लगभग 9500 पेयजल योजनाएं ठप्प हो चुकी हैं। अनेकों घर नदियों में ताश के पत्तों की तरह बिखर चुके हैं, गाडियां तिनकों की तरह जलप्रवाह में बह चुकी हैं। कई पुल जलमग्न हो चुके हैं। चारों ओर चीख-ओ-पुकार, बर्बादी तथा तबाही का मंजर है। जुलाई महीने में भयंकर वर्षा तथा जलप्रपात से केवल कुल्लू तथा मण्डी जिलों में लगभग 4000 करोड़ रुपए के नुकसान का

आकलन था, लेकिन इस बार लगभग पूरे प्रदेश में तथा सभी जिलों में तबाही का आलम है। प्रदेश की सतलुज, व्यास तथा रावी नदियां अपने रौद्र रूप में हैं। चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर, मण्डी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर तथा सोलन जिलों में भयंकर तबाही हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जानमाल तथा सम्पत्ति के नुकसान लेने के लिए निरंतर राज्य प्रशासनिक अधिकारियों, जिलाधीशों तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं कमान पकड़ी है, वे प्रत्येक घटना पर स्वयं जाकर लोगों के आंसू पोंछने का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु प्रकृति के आगे व्यक्ति, व्यवस्था तथा सरकार तो छोटी सी चीज है।

पिछले महीने प्रदेश के 126 जवान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की सातवीं बटालियन द्वारा बठिंडा से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे हैं जिन्हें आपदा से निपटने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन प्रदेश की पहाड़ जैसी आपदाओं को मद्देनजर रखते हुए यह संख्या अपेक्षा से कहीं बहुत कम है। प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों को ही सामान्य सा प्रशिक्षण देकर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है जो कि नाकाफी है। आपदाओं से मुकाबला करने के लिए विधिवत शिक्षित, कौशल प्राप्त एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे आपदाओं का सामना करना असंभव तो नहीं, बल्कि मुश्किल अवश्य होता है। हिमाचल की विकट परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में एक स्थाई एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ आपदा प्रतिक्रिया बटालियन की आवश्यकता है। इससे जहां वास्तविक रूप से प्रशिक्षित लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं पर प्रदेश में आने वाली आपदाओं के नियन्त्रण तथा करोड़ों रुपए के नुकसान की कमी में भी सहायता मिलेगी। किसी भी राज्य के लिए आपदा प्रबंधन एक बहुत ही आवश्यक एवं चुनौतीपूर्ण विषय है। प्रदेश के लोगों की जागरूकता के साथ-साथ विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए इसका प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है।

आपदाओं से सम्बन्धित जानकारी, सूचनाएं, जागरूकता बहुत आवश्यक है ताकि कम से कम सम्पत्ति तथा जान-माल की हानि हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में भी इस अकल्पनीय त्रासदी पर दु:ख प्रकट कर राज्य तथा केन्द्र सरकार के सहयोग से इस पर नियंत्रण पाने का भरोसा जताया है। आवश्यकता है प्रदेश के इस महाप्रलय को केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। इस आपदा के लिए विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान कर मरहम लगाने की आवश्यकता है। इस समय केन्द्र सरकार, विपक्षी दलों तथा सभी लोगों को प्रदेश में आई इस विनाशलीला को समाप्त करने के लिए आर्थिक सहयोग देकर अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। जहां इस मौके पर केन्द्र सरकार से त्वरित आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है वहीं पर भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रतिक्रिया बटालियन की स्थापना भी समय की मांग है।

चिंतन विचार

संबंधों के नवीनीकरण का मौसम

अनजान लोगों से भी थोड़े बहुत संबंध उगाए रखने चाहिए। अपनी योजनाएं बनाने व सपने सच करने के लिए मेहनती चींटी की तरह लगे रहना चाहिए, एक न एक दिन तो सफलता मिलती ही है। चुनावी मरम्मत के मौसम में चाहे नेता एक दूसरे के साथ पुश्तैनी दुश्मनों की तरह व्यवहार करें, बातचीत का स्तर रसातल से भी नीचे ले जाएं लेकिन बात वे लोकतंत्र को अधिक मजबूत करते हुए, देश को अधिक गौरवशाली व अधिक शक्तिशाली बनाने की ही करते हैं। पंचवर्षीय योजना के लगभग सवा चार साल बाद, उन्होंने सामने से आकर हाथ जोड़ मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और बोले, 'अभी भी हम से नाराज़ हैं बड़े भाई।' थोड़ी हैरानी हुई कि यह सज्जन ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनसे अपनी न कोई राजग़ी थी न नाराजग़ी। हमने भी पूरे अदब से हाथ जोडक़र नमस्कार कहा, 'ऐसी कोई बात नहीं है।' अगले क्षण तपाक से समझ में आया कि राजनीति के खेत में चुनाव की स्वादिष्ट एवं उपजाऊ फसल रोपने की तैयारी शुरू हो चुकी है, तभी तो नकली 'प्यार' की असली झप्पियां डाली जा रही हैं। उम्र में हमसे बड़ा होने के बावजूद भी हमें बड़ा भाई बोला जा रहा है। सम्बन्धों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व मानवीय मरम्मत भी धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है। हमारी पत्नी और व्यवस्था ने अच्छी तरह से समझा रखा है कि किसी भी स्तर के राजनीतिज्ञ से नाराजग़ी रखने का वक्त अब कतई नहीं रहा। याद आया, कई बरस पहले हमने उनकी एक हरकत पर टिप्पणी कर दी थी। तब भी पत्नी ने अच्छी तरह से समझाया था कि कहीं यह 'सज्जन' चुने गए तो आपकी खैर नहीं। लेकिन वक्त का शुक्रिया, वह कई पार्टियां बदलने के बावजूद भी हमेशा हारते ही रहे और हम भी बचे रहे। एक बार हमसे पुनः संबंध नवीनीकरण करने के, उनके प्रयास से लगा राजनीति एक अच्छी समझदार अध्यापक भी तो है जो हमें पढ़ाती है कि राजनीति में ही नहीं ज़िंदगी में भी कोई पक्का दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं हुआ करता। अवसर मिले तो अपने खराब सम्बन्धों को ठीक ज़रूर करते रहना चाहिए। अनजान लोगों से भी थोड़े बहुत संबंध उगाए रखने चाहिए। अपनी योजनाएं बनाने व सपने सच करने के लिए मेहनती चींटी की तरह लगे रहना चाहिए, एक न एक दिन तो सफलता मिलती ही है। चुनावी मरम्मत के मौसम में चाहे नेता एक दूसरे के साथ पुश्तैनी दुश्मनों की तरह व्यवहार करें, बातचीत का स्तर रसातल से भी नीचे ले जाएं लेकिन बात वे लोकतंत्र को अधिक मजबूत करते हुए, देश को अधिक गौरवशाली व अधिक शक्तिशाली बनाने की ही करते हैं। यह मौसम होली की तरह होता है जहां सब गले मिल लेते हैं, क्या पता यह गले मिलना कहीं काम आ ही जाए और गले न मिलना कहीं गले ही न पड़ जाए। यह याद रखना ही चाहिए कि नेता यदि लगा रहे तो सांसद न सही विधायक न सही एक दिन पार्षद तो बन ही जाता है और अपने मकान का निर्माण तो करवा ही लेता है। खराब सम्बन्धों की मरम्मत करने में तो वह महा अनुभवी होता ही है। 'घमंड का सिर नीचा' होने का मुहावरा सफल राजनीति में 'घमंड का सिर ऊंचा' हो जाता है। आजकल जब राजनीतिक मरम्मत के हर सधे हुए कारीगर का बाज़ार गर्म है, घमंड का सिर नीचा हुआ घूमता है। राजनीति ने मानवीय जीवन को बहुत लचीला मुहावरा बना कर रख दिया है जिसके असली अर्थ बुरी तरह से टूट-फूट चुके हैं और निरंतर मरम्मत मांग रहे हैं। आचार संहिता के प्रसव काल यानी चुनाव होने तक तक मरम्मत का यह मौसम चलने वाला है। हां, चुनाव के बाद नई सरकारजी के निर्माण हो जाने के बाद घमंड का सिर ऊंचा वाला मुहावरा बाज़ार की शान हो जाएगा।

प्रभात कुमार

रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने दिया 'उद्योग रत्न' अवॉर्ड कारोबारी जगत में योगदान के लिए किया सम्मानित

टाटा ग्रुप के चेयमैन रतन टाटा को उनके कारोबारी जगत में योगदान के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रतन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य कारणों के चलते टाटा इस अवॉर्ड के लिए आयोजित किए जाने वाले समारोह में शामिल नहीं हो सकते थे। इस कारण से उनके घर पर ही एक समारोह आयोजित कर अवॉर्ड दे दिया गया।

नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े कारोबारी और परोपकारी रतन टाटा को शनिवार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित 'उद्योग रत्न' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसके लिए उनके निजी आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार द्वारा रतन टाटा को ये अवॉर्ड दिया गया।

स्वास्थ्य कारणों से अवॉर्ड आवास पर दिया गया

रतन टाटा के स्वास्थ्य कारणों के चलते वे आने वाले इस अवॉर्ड समारोह में शामिल नहीं हो सकते थे। इस कारण से उनके घर पर ही एक समारोह आयोजित कर अवॉर्ड दे दिया गया। इस दौरान रतन टाटा के कारोबार के साथ अन्य क्षेत्रों में दिए गए योगदान को याद किया गया और जश्न मनाया।

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने किया पोस्ट

महाराष्ट्र सरकार ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीसने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह हमारे लिए गर्व को सम्मान का क्षण है। टाटा समूह के अध्यक्ष, पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के पहले 'उद्योगरत्न पुरस्कार - 2023' से सम्मानित किया गया।

क्या है उद्योग रत्न अवॉर्ड?

उद्योग रत्न अवॉर्ड महाराष्ट्र सरकार द्वार शुरू किया गया एक नया पुरस्कार है, जो कि यह सम्मान किसी विशेष क्षेत्र में योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है। इस महाराष्ट्र भूषण अवॉर्ड की तरह है।

इसके द्वारा बिजनेस, इंडस्ट्रीस, शिक्षा, रियल एस्टेट, पर्यटन, फाइनेंसियल सर्विसेज, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, बैंकिंग, आईटी, फूड, हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों में योगदान देने के लिए लोगों को सम्मान दिया जाता है।

Loan Switch Option क्या है? जानिए इससे कैसे कर्ज लेने वाले लोगों को बढ़ती EMI से मिलेगी राहत

RBI की ओर से हाल ही में Loan Switch Option को लेकर बैंकों और रेगुलेटेड संस्थाओं के लिए एक नोटिस निकाला गया है। इसमें कहा गया है कि लोन ग्राहकों को फ्लोटिंग रेट से फिक्स्ड रेट पर स्विच करने का विकल्प ब्याज दरों में बदलाव के समय दिया जाना चाहिए। इससे लोगों को ब्याज दरों में बढ़ोतर के दौरान बढ़ती हुई ईएमआई से राहत मिलेगी।

आरबीआई ने कहा कि ग्राहकों को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। ब्याज दर में बढ़ोतरी के दौरान इससे लोन लेने वालों को फायदा होगा। आरबीआई ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क।

आरबीआई की ओर से बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों से कहा गया है कि ब्याज दरों में परिवर्तन के समय लोन लेने वाले ग्राहकों को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट (Fixed Interest Rate) चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसके लिए आरबीआई द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

आरबीआई ने क्यों लिया ये फैसला?

आरबीआई द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि ब्याज में बढ़ोतरी के दौरान काफी सारे ग्राहकों से शिकायतें मिली थीं कि बैंकों की ओर से बिना कोई सूचना दिए हुए उनकी ईएमआई और लोन की अवधि को बढ़ा दिया गया है।

आरबीआई के इस फैसले का क्या होगा असर?

आरबीआई द्वारा लिए गए इस फैसले का सीधा फायदा लोन लेने लोगों को होगा। इसकी मदद से लोन लेने वाला व्यक्ति ब्याज दर में बढ़ोतरी के समय अपना लोन फ्लोटिंग रेट से हटाकर फिक्स्ड रेट पर स्विच कर सकता है। इससे एक निश्चित समय में होने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर लोन की ईएमआई और अवधि पर कम पड़ेगा। चुने गए निश्चित समय तक लोन की ईएमआई फिक्स रहेगी।

आरबीआई ने नीतिगत ढांचा तैयार करने को कहा

आरबीआई द्वारा जारी नोटिस में बैंकों और सभी रेगुलेटेड संस्थाओं से कहा गया है कि वे इसके लिए सही नीतिगत ढांचा तैयार करें। आरबीआई ने बयान में कहा कि लोन देने के समय रेगुलेटेड संस्थाओं को क्रेडिट लेने वाले व्यक्ति को बेंचमार्क रेट में बदलाव का लोन की ईएमआई और अवधि में प्रभाव को बताना होगा।

CaratLane में 4,600 करोड़ रुपये में 27% हिस्सेदारी खरीदेगी Titan, अक्टूबर तक अधिग्रहण पूरा होने की उम्मीद

टाइटन की ओर से कैरेटलेन में अतिरिक्त 27.18 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। कंपनी द्वारा कहा गया है कि ये अधिग्रहण 31 अक्टूबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। टाइटन टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (TIDCO) का ज्वाइंट वेंचर है। कंपनी तनिष्क मिया जोया और कैरेटलेन ब्रांड का संचालन करता है।

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप के ज्वेलरी ब्रांड टाइटन की ओर से अपनी सब्सिडरी ज्वेलरी कंपनी कैरेटलेन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (CaratLane Trading Pvt Ltd) में 4,621 करोड़ रुपये में 27.18 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला है। इसके बाद कैरेटलेन में टाइटन की हिस्सेदारी बढ़कर 98.28 प्रतिशत हो जाएगी।

बता दें, टाटा ग्रुप की कंपनी की ओर से सचेती और उनके परिवार के सदस्यों के पास मौजूद सभी शेयरों को खरीदने के लिए समझौता किया गया है। इससे टाइटन अपनी ऑनलाइन कारोबार को बढ़ाना चाहती है।

टाइटन को उम्मीद है कि कैरेटलेन का अधिग्रहण 31 अक्टूबर, 2023 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से अपेक्षित नियामक मंजूरी के आधीन है।

कंपनी की ओर से बीएसई फाइलिंग में ये जानकारी दी गई है। टाइटन ने 4,621 करोड़ रुपये में 27.18 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। इसके बाद टाइटन की कैरेटलेन में हिस्सेदारी बढ़कर 98.28 प्रतिशत है।

कैरेटलेन क्या करती है?

कैरेटलेन पूरी तरह से एक ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड है। जो कि ऑनलाइन ही कारोबार करता है। कंपनी किफायती ज्वेलरी पर फोकस है। टाइटन की ओर से कैरेटलेन में 2016 में निवेश करना शुरू किया गया था। पिछले आठ वर्षों की साझेदारी में टाइटन के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क कैरेटलेन में काफी ग्रोथ दर्ज की गई है।

टाइटन का कारोबार

टाइटन टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (TIDCO) का ज्वाइंट वेंचर है। कंपनी तनिष्क, मिया, जोया और कैरेटलेन ब्रांड का संचालन करता है।

टाइटन की ओर से 1987 में घड़ियों के ब्रांड के रूप में पहचान बनाई गई। 1994 में टाइटन ने ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क की शुरुआत है। टाइटन ने मार्च 2023 में 31,897 करोड़ रुपये की आय दर्ज की थी। यह कंपनी के कुल टर्नओवर का 88 प्रतिशत हिस्सा आता है।

भारत में एक लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हुए शुरू, यूनिकॉर्न की संख्या 108 हुई; G20 बैठक में बोले अश्विनी वैष्णव

परिवहन विशेष न्यूज

G20 बेंगलुरु में हुई जी20 की बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में बीते एक दशक में उद्यमशीलता परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। इस कारण स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 100000 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही 108 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने हैं। भारतीय स्टार्टअप्स की वैल्यू 450 अरब डॉलर से अधिक है।

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से कहा कि भारत में उद्यमशीलता परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। देश में तेजी से स्टार्टअप्स की संख्या में इजाफा हुआ है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में हुई G20 की डिजिटल इनोवेशन एलायंस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि, पिछले एक दशक में भारत के उद्यमशीलता परिदृश्य में काफी बड़ा बदलाव आया है। बता दें, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके तहत कई मुद्दों पर अलग-अलग शहरों में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

आगे कहा कि देश में एक दशक पहले 500 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या बढ़कर एक लाख हो गई है और 108 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं। हमारे देश में डेवलपमेंट और इनोवेशन की भावना है, जिससे नए सॉल्यूशन मिलते हैं।

कई देशों के स्टार्टअप शामिल हुए

G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस में बेंगलुरु हुआ और इसमें G20 डीआईए ग्लोबल स्टार्ट-अप विजेताओं को ऑवर्ड दिए गए। इसमें रूस, मिस्र, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, ब्राजील और भारत जैसे कई देशों के स्टार्ट-अप शामिल हुए थे। डीआईए प्रोग्राम में G20 देशों से 174 स्टार्टअप हैं। ये स्टार्टअप एडटेक, हेल्थकेयर, एग्रीटेक, फिनटेक और सिक्योर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर से होते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बेंगलुरु जो कि एक समय ग्लोबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर था। आज भारत के लिए सॉल्यूशंस का प्रोवाइडर बना हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने अपनी क्षमतों का विस्तार किया है। वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन के साथ डिफेंस, रेलवे, हेल्थ, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल और सोरल सेक्टर में काम किया जा रहा है।

इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने कहा कि हमारे स्टार्टप्स की वैल्यू करीब 450 अरब

सेविंग अकाउंट में कितना रख सकते हैं पैसा? जानिए क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम

आज के समय में हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है। क्या आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट पर आपको जो ब्याज मिलता है उस पर भी टैक्स काटा जाता है। ऐसे में कई लोगों का सवाल होता है कि वह अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखें कि उन्हें ब्याज पर कोई टैक्स न देना पड़े। आइए इस आर्टिकल में इस सवाल का जवाब जानते हैं।

नई दिल्ली। आज के समय में बैंक अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। यह कोई भी वित्तीय लेनदेन को आसान कर देता है। डिजिटल बैंकिंग के बाद वित्तीय लेनदेन क्षणभर में हो जाता है। आप सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हर अकाउंट के अपने फायदे होते हैं। ऐसे में एक सवाल आता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं।

सेविंग अकाउंट में कितना कैश रखें

सेविंग अकाउंट में लोग अपनी सेविंग रखते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि वह इस अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप इस अकाउंट में कैश रखने पर कोई लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप इस अकाउंट में सिर्फ उतना ही कैश रखें जो आईटीआर के दायरे में आता है। अगर आप ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है।

आयकर विभाग को क्या जानकारी दे

आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देना होता हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है। इसके साथ ही आप अकाउंट में कितना पैसे रखते हैं। आपके सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट से जो ब्याज मिलता है वह आपके इनकम में जोड़ा जाता है।

उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति की सालाना इनकम 10 लाख रुपये है और उसे ब्याज 10,000 रुपये मिलता है तो उस व्यक्ति का टोटल इनकम 10,10,000 रुपये माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आपके खिलाफ कदम उठाता सकता है।

निवेश पर कैसे हासिल करें अधिक रिटर्न? ये तरीका कर सकता है आपका काम आसान

किसी भी व्यक्ति को निवेश करते समय हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। निवेश के सभी माध्यम जैसे डेट फिक्स्ड इनकम सोना इक्विटी और म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। इससे बाजार के सभी उतार-चढ़ाव का वह फायदा ले सकता है और बाजार में औसत रिटर्न से अधिक रिटर्न हासिल कर सकता है।

नई दिल्ली। निवेश एक काफी पेचीदा कार्य है। किसी भी व्यक्ति को अपना पोर्टफोलियो बनाते समय संतुलन रखना आवश्यक होता है, जिससे कि बाजार के उतार-चढ़ाव का फायदा लिया जा सके और रिटर्न को अधिक किया जा सके।

आज हम अपने अर्टिकल में बताएंगे कि किन निवेश माध्यम से आप अपने पोर्टपोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं।

डेट में निवेश

डेट या फिक्स्ड रिटर्न वाले निवेश को निवेशकों को अपने पोर्टपोलियो में प्राथमिकता देना चाहिए। उदाहरण के लिए पिछले एक साल में ब्याज दर बढ़ने के कारण एफडी में निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला है।

टर्म प्लान

एक टर्म प्लान को निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह देनी चाहिए। इससे निवेशक कोई अनहोनी होने पर परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित कर सकता है। आमतौर पर एक करोड़ से अधिक का टर्म प्लान सही रहता है। टर्म प्लान को आपको नौकरी लगने के तुरंत बाद ही ले लेना चाहिए।

इक्विटी और म्यूचुअल फंड में निवेश

आपको रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक, आपको इक्विटी और म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। इक्विटी में तभी किसी निवेशक को निवेश करना चाहिए, जब उसे बाजार की समझ हो। अन्यथा म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही माना जाता है। इसमें आप एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं।

इमरजेंसी फंड रखें

कई बार देखा जाता है कि आपात परिस्थितियां आने पर इमरजेंसी फंड न होने के चलते लोगों को अपने निवेश में से पैसा निकालना पड़ता है। इससे वित्तीय अनुशासन भी प्रभावित होता है। आप एक बड़ा फंड जमा करने से चूक जाते हैं।

लोन को जल्द से जल्द चुकाए

किसी भी व्यक्ति को अपने अधिक ब्याज वाले लोन को जल्द से जल्द चुकाना चाहिए और उससे बचे पैसे को कही निवेश करना चाहिए, जिससे कि आपको अधिक रिटर्न हासिल करने में मदद मिले।

क्रेडिट स्कोर अच्छा रखें

अधिक रिटर्न हासिल करने के लिए आपको अपने क्रेडिट स्कोर को भी अच्छा रखना चहिए। इससे फायदा ये होता है कि आपको कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा और आप ब्याज पर पैसे बचा सकते हैं। आमतौर पर 750 से अधिक का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है।

'भाजपा कठिन सवाल पहले हल करती है', सत्तारूढ़ पार्टी की चुनावी रणनीति पर विश्लेषकों की राय

परिवहन विशेष न्यूज

लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर सियासत जारी है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जो इतनी जल्दी उम्मीदवारों का एलान किया है, उसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान किया है। इनके राजनीति पर असर और इनके संदेशों पर 'खबरों के खिलाड़ी' की इस कड़ी में मजेदार चर्चा हुई।

नई दिल्ली। इस हफ्ते देश की आजादी का जश्न और लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण खबरों में रहा, वहीं कुछ राज्यों में भाजपा के उम्मीदवारों की सूची को लेकर भी खूब चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से साफ कहा कि अगले साल भी झंडारोहण वहीं करेंगे। उस पर सियासत हो रही है और पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो कहा, क्या वह उनका विश्वास है या अति आत्मविश्वास?

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने कुछ उम्मीदवारों का एलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 21 और मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों के नाम का एलान हो चुका है। इन्हीं मुद्दों पर 'खबरों के खिलाड़ी' के विश्लेषकों ने अपने विचार रखे।

'खबरों के खिलाड़ी' की इस कड़ी में आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद रहे वरिष्ठ विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री, पूर्णिमा त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, बिलाल सब्जवारी, संजय राणा और गुंजा कपूर। इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा को अमर उजाला के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर शनिवार रात नौ बजे लाइव देखा जा सकेगा। आइए पढ़ते हैं इनकी चर्चा के कुछ प्रमुख अंश...

पूर्णिमा त्रिपाठी

'यह प्रधानमंत्री का अति आत्मविश्वास नहीं है, वे हमेशा से ही इसी विश्वास के साथ बोलते रहे हैं। मजेदार बात ये रही कि उन्होंने साफ तौर पर खुद को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और इस तरह से उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को नकार दिया, जिसमें सांसद नेता का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में युवाओं, महिलाओं की बात की और साथ ही पसमांदा मुस्लिमों के बारे में बात की। इसके साथ ही उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अगले चुनाव में उनका लक्ष्य किन मुद्दों पर रहने वाला है? इनमें परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे शामिल हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट की बात करें तो भाजपा की रणनीति में थोड़ा बदलाव तो हुआ है। कर्नाटक चुनाव में हार इसकी वजह हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा उम्मीदवारों के नामों का एलान कर चाहती है कि पहले से तैयारी की जा सके।'

गुंजा कपूर

'मतदाता और करदाता देश को बनाते हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री लाल किले से अपने भाषण में किसानों, टैक्सपेयर की बात करते हैं तो इसमें क्या गलत है? प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अगले साल भी आएंगे, दरअसल वे देश को एक उम्मीद देना चाहते हैं। लाल किले से दिए जाने वाले प्रधानमंत्री के भाषण से ऐसी आशा की भी जाती है कि वे देशवासियों को एक उम्मीद दें, सपने दें। पीएम मोदी अपने कार्यकाल से आगे की बात करते आए हैं और इसमें कुछ भी सियासी नहीं है। अगर कोई नेता है तो उन्हें राजनीति तो करनी ही है तो स्वतंत्रता दिवस के भाषण की आलोचना करना गलत है.... । जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती हैं, वैसे ही आप अपनी रणनीति बदलते हैं। कर्नाटक में भाजपा ने अपने कुछ उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया और वो कांग्रेस में चले गए, जिसका भाजपा को नुकसान हुआ। अब भाजपा की रणनीति में बदलाव दिख रहा है। भाजपा अपने कमजोर इलाकों पर फोकस कर रही है।'

बिलाल सब्जवारी

'प्रधानमंत्री मोदी का जो व्यक्तित्व है, वह विपक्षी दलों पर हावी है, लेकिन जहां तक परंपरा की बात है तो अटल बिहारी वाजपेयी जिस परंपरा में विश्वास करते थे, उसमें हमेशा समग्र भारत के साथ ही विपक्ष के प्रति नरम और लचीला रवैया होता था। वह उनकी समावेशी राजनीति थी। वहीं, पीएम मोदी की राजनीति अलग तरह की है। कभी-कभी उनका विश्वास, अति-आत्मविश्वास में बदलता नजर आता है। जब वे विपक्ष पर हमलावर होते हैं तो उसमें वे अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा का निर्वहन करने में नाकाम दिखते हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर सिर्फ विपक्षी दलों पर आरोप लगा देना सही नहीं है। पीएम मोदी की राजनीति में इंदिरा गांधी की छाप है और अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति पर पंडित नेहरू का प्रभाव था।'

'जहां तक राजनीति में प्रयोगों की बात है तो भाजपा इसमें आगे रही है। कर्नाटक नतीजों के बाद यह बदलाव आया है। पार्टी को जिन सीटों पर कमजोर फीडबैक मिला है, उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। भाजपा सोशल इंजीनियरिंग की माहिर खिलाड़ी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय क्षत्रप, पार्टी कैडर की पकड़ जैसे मुद्दे पर भी जीत मिलती है।'

संजय राणा

'प्रधानमंत्री मोदी दूरदर्शी नेता हैं और यह बात उनके भाषणों में दिखती हैं। गांधी जी जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि देश कब आजाद होगा, लेकिन वे इसके लिए संघर्ष करते रहे। उसी तरह प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से बात करते हुए राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे थे। 2014 का चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और 2019 का चुनाव भी। अब 2024 का चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा और जनता के इस विश्वास को पीएम मोदी बखूबी समझते हैं। इंदिरा गांधी के बाद सबसे बड़े जननेता पीएम मोदी ही हुए हैं... । भाजपा ने कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का एलान इसलिए किया है ताकि उन पर ज्यादा मेहनत की जा सके और बेहतर तरीके से फोकस किया जा सके। कर्नाटक से सबक लेकर रणनीति में यह बदलाव किया गया है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार का चेहरा अहम होता है, इसलिए भी भाजपा ने अपनी रणनीति में यह बदलाव किया है।'

विनोद अग्निहोत्री

'मौजूदा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री स्वभाविक रूप से अगले चुनाव के लिए चेहरा होते हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण में जो विशेषता थी, वो ये कि उनका ये भाषण पूरी तरह से 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर दिया गया। प्रधानमंत्री जानते हैं कि सामने वाले का मनोबल कब और कैसे तोड़ना है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी और अब लाल किले से भी उन्होंने जो भाषण दिया है, उसने विपक्ष का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। पीएम के आत्मविश्वास का कारण, भाजपा जैसे मजबूत संगठन वाली पार्टी, आरएसएस जैसा संगठन, उनका लोकप्रिय चेहरा जैसे कारक हैं। हालांकि, पीएम मोदी के लाल किले से दिए भाषण में वैश्विक अपील का अभाव था, यह भाषण चुनाव तक सीमित रहा।'

'भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले के विधानसभा चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। भाजपा ने इस बार उम्मीदवारों को पूरा समय दिया है चुनाव की तैयारियों का। साथ ही इससे डैमेज कंट्रोल का समय मिल जाएगा। भाजपा नहीं चाहती कि विधानसभा चुनाव की हार से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बुरा असर पड़े। यही वजह है कि भाजपा ने इस बार चुनाव की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है।'

हर्षवर्धन त्रिपाठी

'राजनीति हो या जीवन का कोई भी पक्ष, हर जगह सरप्राइज अहम होता है। अगर आप विपक्षी को चौंकाने की ताकत रखते हैं तो यह अहम बात है। संघ, भाजपा के विचार के लिए मध्य प्रदेश अहम है। भाजपा कठिन सवाल पहले हल करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है जल्द उम्मीदवारों का एलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा, कांग्रेस के सामने टिकती नहीं दिख रही है। वहां भाजपा नेतृत्व के अभाव से जूझ रही है।'

'भाजपा के लिए राजस्थान आसान है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर अमित शाह का फोकस है। मध्य प्रदेश में फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा हैं और वहां भाजपा के लिए संकट, चेहरे का नहीं, संतुलन का है। भाजपा ने एमपी में जिन नेताओं को टिकट दिया है, वो जिला स्तर के नेता हैं और उनके पास खुद के 20-25 हजार वोट हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा को उम्मीद है कि उनकी सरकार ने जो आदिवासियों के लिए काम किए हैं और आदिवासी वर्ग से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है, उसका पार्टी को फायदा मिलेगा।'

अधीर रंजन ने बंगाल में कानून-व्यवस्था को लेकर दागे सवाल, प्रधानमंत्री के बारे में कह दी बड़ी बात

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकता है, चाहे वह प्रियंका गांधी हो या कोई और हो। प्रधानमंत्री अगर इतने बेफिक्र रहते हैं तो आपको इस पर इतनी चिंता क्यों हो रही है आपके खिलाफ चुनाव में कौन खड़ा होगा।

मानसून सत्र के बाद से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का चर्चा में हैं। वे लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बात की जा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगर प्रियंका गांधी को उतारा जाए तो जीत हासिल करेंगे। इस पर जब अधीर रंजन से सवाल पूछा गया तो बोले कि कांग्रेस का रुख सबको पता है, अगर कांग्रेस कभी अपना रुख बदलेगी तो हम इसके बारे में बता देंगे।

आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकता है, चाहे वह प्रियंका गांधी हो या कोई और हो। प्रधानमंत्री अगर इतने बेफिक्र रहते हैं तो आपको इस पर इतनी चिंता क्यों हो रही है आपके खिलाफ चुनाव में कौन खड़ा होगा।

बंगाल में रैगिंग को प्रतिबंधित करना चाहिए

जादवपुर छात्र मौत मामले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल के शिक्षण प्रतिष्ठान के हालात खराब होते जा रहे हैं जिसका उदाहरण जादवपुर विश्वविद्यालय में घटी यह घटना है। कानून-व्यवस्था नहीं है। जादवपुर विवि 5-स्टार विवि में से एक माना जाता रहा है लेकिन आज इसे रैगिंग के लिए जाना जा रहा है जो शर्म की बात है। बंगाल की सरकार को तुरंत कानून पारित करके रैगिंग को प्रतिबंधित करना चाहिए।

टीएमसी नेता के दामाद कांग्रेस में शामिल

पूर्व टीएमसी युवा नेता और टीएमसी नेता और राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम के दामाद यासर हैदर कोलकाता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- पंचायत सदस्यों के लिए दो बच्चों की सीमा में जैविक संतानें होंगी शामिल

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शनिवार को फैसला सुनाया कि महाराष्ट्र में पंचायत सदस्यों के लिए निर्धारित दो बच्चों की सीमा में केवल जैविक संतानें शामिल होंगी, सौतेले बच्चे नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शनिवार को फैसला सुनाया कि महाराष्ट्र में पंचायत सदस्यों के लिए निर्धारित दो बच्चों की सीमा में केवल जैविक संतानें शामिल होंगी, सौतेले बच्चे नहीं। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम उन लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव (ग्राम पंचायत से नगर निगम) लड़ने से अयोग्य घोषित करता है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की खंडपीठ ने खैरुनिसा शेख चंद की याचिका पर एकल पीठ द्वारा सुनवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में उनकी अयोग्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उनके तीन से अधिक बच्चे हैं। एकल पीठ ने यह स्पष्ट करने के लिए मामले को खंड पीठ के पास भेज दिया कि क्या महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के प्रावधानों में 'दो बच्चे' शब्द का उपयोग सामान्य अर्थ में सौतेले बच्चों को शामिल करने के लिए किया गया है या सीमित अर्थ में केवल व्यक्ति से पैदा हुए बच्चों को शामिल करने के लिए किया गया है।

केरल के वित्त मंत्री बालगोपाल ने साधा निशाना, बोले- राज्य को केंद्र से अपना राजस्व हिस्सा नहीं मिल रहा

केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा है कि राज्य को केंद्र से अपना राजस्व हिस्सा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्र से मिलने वाले अनुदान में 80 फीसदी की कटौती की गई है।

केरल सरकार ने केंद्र सरकार पर राजस्व को लेकर करारा हमला किया है। केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा है कि राज्य को केंद्र से अपना राजस्व हिस्सा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्र से मिलने वाले अनुदान में 80 फीसदी की कटौती की गई है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं।

केएन बालगोपाल ने लगाया भारी असमानता आरोप

केएन बालगोपाल ने कहा है कि कुल राजस्व आय में से, पहले केरल को केंद्र सरकार के हिस्से से लगभग 45 फीसदी और राज्य से 45 फीसदी मिलता था। यह अखिल भारतीय औसत है। अब केरल लगभग 70 फीसदी भुगतान कर रहा है और केंद्र से केवल 30 फीसदी से कम आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें भारी असमानता है और यह भेदभाव है, लोकसभा में यूडीएफ के करीब 18 सांसद हैं, लेकिन वे लोगों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी केरल से सांसद हैं लेकिन कांग्रेस केरल के मुद्दों पर ओछी राजनीति कर रही है।

इससे पहले, बालगोपाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र केरल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है और केरल की वायनाड लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी के नेतृत्व वाले यूडीएफ सांसद राज्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि, राज्य के वित्तीय संकट का सामना करने के बावजूद, एलडीएफ सरकार ने सभी क्षेत्रों में सहायता का आश्वासन दिया है और ओणम सत्र के दौरान लगभग 19,000 करोड़ रुपये खर्च करने की उम्मीद है।

कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज

केरल के वित्त मंत्री बालगोपाल ने आरोप लगाया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि यूडीएफ सांसद केरल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश में भाजपा के साथ हैं। इसके बाद कांग्रेस ने केरल के वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए असहयोग के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें इस उद्देश्य के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, सबसे पहले, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि केंद्र राज्य को धन देने से इनकार क्यों कर रहा है।

केरल कर्ज के जाल में फंस गया है

कांग्रेस विधायक और पूर्व केरल नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्नितला ने कहा कि केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल राज्य में वित्त प्रबंधन में पूरी तरह से विफल रहे हैं। केरल कर्ज के जाल में फंस गया है, सरकार को पता नहीं है कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। फिर भी, वह कांग्रेस सांसदों को दोष दे रहे हैं, मुझे आश्चर्य है कि कैसे वह इस मुद्दे के लिए कांग्रेस को दोषी ठहरा सकते हैं, हम राज्य पर शासन नहीं कर रहे हैं।

नगर निगम ने ध्वस्त किया भगवा नेता के घर के बाहर का अवैध ढांचा, TMC और BJP आए आमने-सामने

परिवहन विशेष न्यूज

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच शनिवार को उस समय आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जब शहर के नगर निकाय ने भगवा पार्टी के एक नेता के घर के बाहर बैठने की व्यवस्था करने वाले अवैध ढांचे के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया।

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच शनिवार को उस समय आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जब शहर के नगर निकाय ने भगवा पार्टी के एक नेता के घर के बाहर बैठने की व्यवस्था करने वाले अवैध ढांचे के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया।

इसके बाद सजल घोष के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) मुख्यालय में शोर-शराबा किया और तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों ने उनका विरोध किया, जिससे

लगभग हिंसक झड़प की स्थिति बन गई।

भाजपा पार्षद सजल घोष ने दावा किया कि शहर के उत्तरी हिस्से में बीडन स्ट्रीट पर पार्टी की कोलकाता जिला समिति के नेता सुनील सिंह के घर पर निर्माण कार्य को केएमसी के दस्ते ने राजनीतिक प्रतिशोध में ध्वस्त कर दिया। घोष ने कहा, '2021 के विधानसभा चुनाव के बाद शहर के श्यामपुकुर निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के आतंक के शासन के खिलाफ प्रदर्शन करने की हिम्मत करने पर स्थानीय टीएमसी पार्षद ने सिंह को निशाना बनाया।'

इलाके के टीएमसी पार्षद तारकनाथ चटर्जी ने आरोप से इनकार करते हुए कहा, 'घटना में कोई राजनीति नहीं है और केएमसी ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए कुछ ढांचे के एक हिस्से को ध्वस्त किया।'

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, योगी आदित्यनाथ के शासन में उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों और अपराधियों द्वारा बनाए गए अवैध ढांचों को गिराने के लिए अर्थमूवर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर से लेकर शहर के बीचोंबीच बीडन स्ट्रीट तक हर जगह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस शासित केएमसी द्वारा तोड़फोड़ के विरोध में सड़क पर उतरेगी।

हंगरी के नागरिक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी

धोखाधड़ी से दो लाख निवेशकों से जमा कराए 1,000 करोड़

आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) ने एक हंगरी के नागरिक के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शनिवार को एक बयान में बताया कि व्यक्ति एक क्रिप्टो-पोंजी फर्म का प्रमुख है।

आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) ने एक हंगरी के नागरिक के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शनिवार को एक बयान में बताया कि व्यक्ति एक क्रिप्टो-पोंजी फर्म का प्रमुख है, जो कथित तौर पर निवेशकों को उनके पैसे से धोखा देने में शामिल है। इसमें कहा गया है कि एसटीए टोकन नाम की कंपनी पर पोंजी कारोबार चलाने और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अनुमति के बिना देशभर में दो लाख लोगों से करीब 1,000 करोड़ रुपये जमा कराने का आरोप है। बयान में कहा गया है कि कथित घोटाले की जांच कर रही ओडिशा की आर्थिक अपराध शाखा के अनुरोध पर लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। कंपनी के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और इनामी चिट और धन परिचालन योजना (पाबंदी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बताया कि इस घोटाले में दूसरे विदेशी डच नागरिक की संलिप्तता की जांच की जा रही है।

आर्थिक अपराध शाखा ने कहा, एसटीए टोकन के प्रमुख हंगरी के डेविड गेज ने पर्यटक वीजा पर 2022-23 में भारत में दो बार प्रवेश किया था और ओडिशा, गोवा, पंजाब, झारखंड और दिल्ली जैसे विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए लगभग पच्चीस दिनों तक देश में रहा था। पहली बार उसने अमेरिका और तुर्की के रास्ते भारत की यात्रा की थी और दूसरी बार पोलैंड के रास्ते भारत की यात्रा की थी। उसने ओडिशा में भुवनेश्वर और भद्रक की यात्रा की।

ईओडब्ल्यू ने कहा कि मामला दर्ज होने के बाद गेज ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया, लेकिन उसके भारतीय सहयोगी अभी भी उसकी एआई द्वारा बनाई तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल करके यूट्यूब वीडियो जारी कर रहे हैं। घोटाले के कुछ शीर्ष खिलाड़ी यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म में प्रचार गतिविधि भी कर रहे हैं और निर्दोष निवेशकों को धोखा देना जारी रखे हुए हैं। उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, पर्यटक वीजा वाले लोगों के लिए व्यापार और प्रचार गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं है।

अधिकारी ने कहा कि ईओडब्ल्यू मामले में कानूनी कार्रवाई के अलावा आवश्यक कार्रवाई के लिए विदेश मंत्रालय को मामले की रिपोर्ट देगा। ईओडब्ल्यू ने इससे पहले एसटीए टोकन के देश और राज्य प्रमुख गुरतेज सिंह सिद्धू और निरोद दास को सात अगस्त को राजस्थान और भद्रक से गिरफ्तार किया था। भुवनेश्वर के एक निवेश सलाहकार और वित्तीय सलाहकार को भी 15 अगस्त को पकड़ा गया था।

कर्नाटक: विधान परिषद के सदस्य नामित किए गए पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री एमआर सीताराम और उमाश्री और पूर्व ईडी अधिकारी एचपी सुधाम दास को कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया।

पालघर में एक डेवलपर पर हमला मामले में पुलिस ने एक दबोचा; ठाणे में किशोर की पीट-पीटकर हत्या

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई इलाके में एक डेवलपर पर दो महीने पहले कुछ लोगों ने हमला किया और उससे जबरन वसूली की मांग की गई थी। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि डेवलपर हमला मामले में एक और व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई इलाके में एक डेवलपर पर दो महीने पहले कुछ लोगों ने हमला किया और उससे जबरन वसूली की मांग की गई थी। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि डेवलपर हमला मामले में एक और व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अब इस मामले में पकड़े आरोपियों की संख्या तीन हो गई है जबकि मामले का मुख्य आरोपी फरार है। अधिकारी ने आगे बताया कि मीरा भयंदर-वसई विरार पुलिस की अपराध इकाई के अधिकारियों ने गुरुवार को मुंबई के गोरेगांव से गिरीश नायर को गिरफ्तार किया। अपराध इकाई के वरिष्ठ निरीक्षक प्रमोद बदख ने कहा कि इस साल 21 जून को वसई तालुका के जुचंद्रा स्थित डेवलपर के कार्यालय में चार लोग तलवार लेकर घुस आए थे और डेवलपर और उसके कर्मचारियों पर हमला कर दिया था साथ ही उनसे जबरन वसूली की मांग की थी। इसके बाद शिकायत के आधार पर नायगांव पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 386 (जबरन वसूली), 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 452 (घर में अतिक्रमण), 143 (गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा) के तहत मामला दर्ज किया था।, 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी), 120-बी (आपराधिक साजिश), इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने अब आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया है और मुख्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जल्दी ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959.
किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये मसौदे के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023